[Shri Satya Narayan Sinha]

the Table of the House on the 28th March, 1961.

**Shri D. C. Sharma:** (Gurdaspur): By whom?

**Shri Satya Narayan Sinha:** I think both of them stand in the name of the hon. Member.

---

**12.12 hrs.**

## GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

**Mr. Speaker:** The House will now proceed with the general discussion of the General Budget. Shri Koratkar.

**श्री कोरटकर** ( हैदराबाद ) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं एक घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करा रहा था जिसका जिक्र मेरी अपनी राय में माननीय वित्त मंत्री के भाषण में आना चाहिये था मगर उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया ।

**Mr. Speaker:** The hon. Member will kindly resume his seat. I would like to know this from the hon. Finance Minister. Ten hours have been allotted for the General Discussion. We have already taken Four hours and forty minutes. Today, five hours and twenty minutes remain. We are now starting at a quarter past 12. This will last till 5.30. Does he want to conclude it today or will he reply on Monday?

**The Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** Today.

**Mr. Speaker:** The House will then sit till 6 o'clock.

**Some Hon. Members:** No.

**Shri Morarji Desai:** This may be over before that. There are not many speakers: I do not know.

**Mr. Speaker:** Very well; we will conclude this today. Five hours and ten minutes more. That means that we will have to conclude this by 5.30, at the most. How long will the hon. Finance Minister take?

**Shri Morarji Desai:** Forty minutes.

**Mr. Speaker:** I will call him at 4.30.

**Shri Morarji Desai:** Yes.

**Mr. Speaker:** The hon. Member might continue.

**श्री कोरटकर** : वह घटना जिसकी तरफ में इशारा कर रहा था वह ब्रिटेन का इरादा है जिसके जरिये वह कामन मारकेट में शरीक होना चाहता है । इस इरादे के जाहिर होने पर राष्ट्र मंडल के सभी देशों में एक प्रकार की हल चल मची थी और सब की तरफ से इसका इस कारण विरोध हो रहा था कि इसकी वजह से ब्रिटेन में राष्ट्र मंडल के देशों के—जिन में भारत भी शरीक है—जो बहुत से पदार्थ बिना किसी कर के या कम कर देकर निर्यात किए जाते हैं उनके निर्यात को ब्रिटेन के कामन मारकेट में शरीक हो जाने से बड़ा धक्का लगेगा । ब्रिटेन के इस प्रकार योरोपीय कामन मारकेट में शामिल हो जाने के कारण हमारा निर्यातजिस पर हम बहुत कुछ निर्भर करते हैं या बन्द हो जाएगा या कम हो जाएगा । यह घटना अगले वित्तीय वर्ष में होने वाली है अतः मेरे अपने विचार से वित्त मंत्री जी को अपने भाषण में उस पर प्रकाश डालना चाहिये था कि क्या इस के कारण हमारे व्यापार को कुछ नुकसान होने वाला है या नहीं ? और क्या भारत वर्ष को इसका विरोध करना चाहिये ? यद्यपि वित्त मंत्री के भाषण में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तथापि क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पर जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा, मैं दो चार शब्द सदन के सामने कहना चाहता हूं ।

इसके विचार के लिये हमें दो तरह से देखना पड़ता है, एक तो ब्रिटेन को लक्ष्य में रख कर इसको देखना पड़ेगा और दूसरे

भारत को लक्ष्य में रख कर इसको देखना पड़ेगा ।

जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, स न को यह मालम है कि जब कामन मारकेट की सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए थे तो हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों ने ब्रिटेन को भी इसके लिए आमंत्रित किया था । किन्तु ब्रिटेन ने उस समय राष्ट्र मंडल के साथ अपने सम्बन्धों को देखते हुए इस बात से इन्कार किया । मगर चार वर्ष के अन्दर ही कुछ ऐसी स्थिति आ अई कि ब्रिटेन को यह मालूम होने लगा कि उसका जो निर्णय कामन मारकेट में शरीक न होने के बारे में किया गया था, वह उसके लिये घातक साबित हो रहा है । ब्रिटेन के निर्यात का ६० प्रतिशत हिस्सा इन्हीं संघीय देशों के साथ रहा करता था । चार वर्ष में यह निर्यात व्यापार घट कर ४० प्रतिशत रह गया इसी प्रकार से इन संघीय देशों उत्पादन शक्ति बहुत बढ़ गई है और उसका भी ब्रिटेन की उत्पादन शक्ति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है जहां इन संघीय देशों की उत्पादन शक्ति दो वर्ष के अन्दर २० प्रतिशत बढ़ी है वहां ब्रिटेन की केवल ८ फी प्रतिशत बढ़ी है : इसके साथ ही साथ जो बड़ी बात देखने की है वह यह है कि यह कामन मारकेट सिर्फ आर्थिक व्यवस्था की ही चीज रहने वाली नहीं है बल्कि यह एक राजनीतिक चीज बनने जा रही है । ऐसा मालम होता है कि आगे आने वाले जमाने में यह संघ यूनाइटेड स्टेट्स आफ यूरोप बनने जा रहा है । इन सब चीजों की देखते हुये ब्रिटेन को डर मालूम हुआ कि कहीं वह सबसे अलग ही न रह जाए । इस प्रकार उसके सामने अपनी आत्म रक्षा का सवाल था । इस को देखते हुये यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन कामन मरकेट में जरूर शरीक होगा । भारत या राष्ट्र मंडल के किसी दूसरे देश का इसके लिये विरोध करना एक बेकार सी चीज है । यह स्थिति ब्रिटेन को आर्थिक जगत में जीवित रहने के लिये मंजर करनी पड़ी है । ऐसी हालत में हमको केवल यही देखना होगा कि ब्रिटेन के इस तरह से कामन मारकेट में जाने के बाद हमारे व्यापार पर इसका क्या असर हो सकता है ? आया वह असर खराब होगा या कोई खास असर नहीं होगा ?

जहां तक मैं देखता हूं भारत से ब्रिटेन को जो चीजें निर्यात की जाती हैं उनमें चाय, जूट के पदार्थ, कपड़ा, चमड़ा, मैंगनीज, ऊनी कालीन और वनस्पति तैल आदि मुख्य हैं । मैं इस चीज की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे निर्यात व्यापार का करीब २५ प्रति शत हिस्सा ब्रिटेन के साथ है । उसकी मात्रा लगभग २०० करोड़ रुपये सालाना की है । इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर संघीय देशों से भी किसी प्रकार का आयात कर नहीं है । उन चीजों को छोड़ दिया जाये तो बहुतसी दूसरी चीजें ऐसी हैं जिनमें कि हमारा कोई प्रतिद्वन्दी देश नहीं है । इस प्रकार की दो बड़ी चीजें हैं, एक तो चाय और दूसरा जूट और जूट के बने हुए पदार्थ । चाय का व्यापार ही हमारा ब्रिटेन के साथ सबसे बड़ा व्यापार है । करीब २०० करोड़ के व्यापार में ८२ करोड़ का व्यापार चाय का ही है । यह बहुत बड़ी राशि का व्यापार है और इसी के लिये आशंका पैदा हो रही है कि इस व्यापार पर बुरा असर न हो ?

जहां तक मैं देखता हूं मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस व्यापार में हमारा कोई प्रतिद्वन्दी देश न होने के समान है । अतः इस पर भी कोई बड़ा भारी असर पड़ेगा ऐसा नजर नहीं आता । केवल एक सीलोन ही ऐसा देश है जो हमारे अतिरिक्त ब्रिटेन में चाय भेजता है, लेकिन उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी कि भारत की है । अर्थात् वह भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है । अतः वह कोई खास असर नहीं पैदा कर सकता ।

[श्री कोरटकर]

इसके साथ ही साथ जूट और जूट के पदार्थ जो ब्रिटेन में भेजे जाते हैं, उन पर भी यही बात लागू होती है । इस मामले में हमारा प्रतिद्वन्दी देश पाकिस्तान ह, वह भी राष्ट्र-मंडल का सदस्य होने के कारण जूट व उसके पदार्थों के निर्यात पर भी ब्रिटेन के कामन मार्केट में शरीक होने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा नजर नहीं आता है ।

हम जानते हैं कि चाय पीना सभ्य देशों के निवासियों का एक व्यसन बन गया है । वह यों ही छूट नहीं सकता । हमें इस बात की आशा करनी चाहिये कि थोड़े से करों को बढ़ाने से इंग्लैंड में न तो चाय पीने वाले लोग ही कम हो जायेंगे और न ही चाय पीने वाले कम चाय पीयेंगे ।

इसके बाद कपड़ा और वनस्पति तेल रह जाता है । कपड़े के बारे में मुझे यह कहना है कि आयात-करों के होते हुए भी जापान अब भी इंग्लैंड के बाजार में हमारे साथ बहुत ही बुरी तरह से मुकाबला कर रहा है । उसको देखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे यहां कपड़े के बनाने में ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है और हमारी मिलें पुरानी होने की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा कपड़ा जापान के कपड़े से महंगा पड़ता हो । आवश्यकता इस बात की है कि उन मिलों में आजकल के जमाने को देखते हुए तरक्की करके कपड़ा बनाने के खर्च को कम किया जाये, न कि ब्रिटेन के कामन मार्केट में जाने से डरना चाहिये ।

इस प्रकार अगर देखा जाए, तो स्पष्ट होगा कि ब्रिटेन के कामन मार्केट में शामिल होने से हम पर बहुत ही थोड़ा असर होगा । कपड़े और वनस्पति तेल के क्षेत्र में करीब-करीब सोलह करोड़ रुपये के व्यापार पर उसका असर पड़गा । उससे हमें घबराने का कोई कारण है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है ।

अब कामन मार्केट के कारण संघीय देशों में जो तरक्की हुई है उससे हमें क्या सीखना चाहिए, वे दो बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह एक तथ्य है कि कामन मार्केट ने थोड़े समय में अपने आन्तरिक व्यापार में बड़ी भारी तरक्की की है और इस प्रकार इस बात को साबित किया है कि आने वाले जमाने में छोटे-छोटे देश आर्थिक मुकाबले में टिक नहीं सकते हैं । देशों का विस्तृत होना बहुत जरूरी है, बड़े देश ही आने वाले ज़माने में टिक सकते हैं और वहीं पर उत्पादन की बड़ी वृद्धि हो सकती है । सौभाग्य से भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है—एक महाद्वीप के बराबर है और बहुत सम्भव है कि यहां पर जो दो बड़ी-बड़ी पंचवर्षीय योजनायें कामयाब हुई हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है ।

कामन मार्केट की सफलता ने बहुत जोर के साथ इस बात को हमारे सामने रखा है कि यदि हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है, तो हमें उसकी एकता को बचाना चाहिए । हम शोक से देखते हैं कि हमारे अन्दर इस बारे में कुछ विघातक प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं । पहले जातीयता तो थी ही, अब प्रान्तीयता भी सिर उठा रही है । एक बड़ी बात यह है कि आर्थिक मामलों में प्रान्तीयता बहुत जोर पकड़ रही है । हर एक प्रान्त यह चाहता है कि वही अपने रीसोर्सिज से ज्यादा स ज्यादा फ़ायदा उठाए । यह प्रवृत्ति हमको उन्नति की तरफ जाने से रोकेगी ।

इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । आसाम में एक आयल कम्पनी को इसलिए प्रास्पेक्टिंग लायसेंस नहीं मिल रहा है कि सेंटर के साथ उस का रायल्टी के बारे में तसफ़िया नहीं हो रहा है । इस तरह से आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कई सालों से नदियों के पानी का

सवाल पड़ा हुआ है और उसकी वजह से बहुत बातें रुकी हुई हैं । महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगांव का प्रश्न उतना ही पेचीदा बना है, जितना कि चीन और भारत में काश्मीर के एक भाग का प्रश्न है । इन प्रवृत्तियों को रोका जाना बहुत जरूरी है और इन समस्याओं का फैसला जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, कामन मार्केट यह एक बहुत बड़ी बात हमको सिखा रही है ।

अब मैं एक और बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि कामन मार्केट हमको सिखा रही है । शायद इस सदन को यह अजनबी बात मालूम हो, लेकिन उस पर भी विचार होना जरूरी है । प्रश्न यह है कि इस जमाने में हमें अपने एक्सपोर्टस को बढ़ाने की तरफ इतना चिन्तित होने की आवश्यकता है या नहीं जितना कि हमें नजर आ रहा है । एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की स्पीच में भी बहुत कुछ कहा गया है । उसके अलावा गत पांच सालों में इस बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है । इतना करते हुए भी हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, यह भी एक वाकया है । अगर इसके कारणों पर हम ध्यान दें, तो ज्ञात होगा कि मशीनों जैसी बड़ी-बड़ी चीजें विकसित देशों में कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीजें वहां पर हमसे अच्छी और पहले से ही मौजूद हैं और अविकसित देशों में उनको लेने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनमें ये चीजें खरीदने की क्षमता नहीं पैदा हुई है । इसलिए चाय, काफी, ऊनी कालीन और दूसरी छोटी छोटी चीजें भेज कर हम कितना एक्सपोर्ट कर सकेंगे और कितना फ़ारेन एक्सचेंज कमा सकेंगे, यह बड़ा भारी प्रश्न है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट्स से अपने देश की तरक्की करना एक पुराने जमाने का, साम्राज्यवादी विचार है । जो-जो देश विकसित होते जा रहे हैं, वे चाहते हैं कि अपने यहां इम्पोर्ट्स को बन्द किया जाये और आहिस्ता-आहिस्ता यह विचार बढ़ता जायेगा । जब सब देश अपने इम्पोर्टस् को बन्द करना चाहेंगे, तो उस वक्त एक्सपोर्ट्स कैसे ज्यादा किये जा सकते हैं, यह भी बड़ा भारी विचारणीय प्रश्न है । इस वक्त सिवाय वेस्ट जर्मनी के कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है, जिसका ट्रेड बैलेंस वृद्धि की तरफ दिखाई देता हो । हम देखते हैं कि बड़े बड़े देशों के एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अविकसित देशों को मदद करने के लिये भेजा जाता है । उनके यहां जो ज्यादा पैदावार होती है, जो खप नहीं सकती है उसको किस रूप में दूसरे देशों को दिया जाये, इसी बात की तरफ ज्यादा तवज्जह दी जा रही है । ऐसी सूरत में एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बातें करना एक व्यर्थ बात है ।

साझे बाजार की जो उन्नति हुई है, वह इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उसको बनाने वाले देशों का आपसी व्यापार बहुत बढ़ा है और उनके यहां जो उत्पादन बढ़ा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपस के व्यापार मे ही खर्च हो गया है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि जो कुछ हम उत्पन्न करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट में भेजा जाये, इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि अपने देश के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाये ताकि जो कुछ हम पैदा करते हैं, उस को हम अपने देश में ही खपा सकें । इससे हमारा स्टेंडर्ड आफ लाइफ़ बढ़ सकता है ।

कल श्री आसर ने करों के सम्बन्ध में जिस बात की तरफ़ तवज्जह दिलाई, मैं उसका अनुमोदन करता हूं । उन्होंने कहा कि नये करों को लगाने के बजाये अगर करों को वसूल करने की तरफ़ ज्यादा तवज्जह दी गई, तो हमारी बहुत कुछ कठिनाइयां कम हो जायेंगी । उन्होंने सदन के सामने एक उदाहरण रखा था कि इनकम टैक्स की

[श्री कोरटकर]

वसूली के सम्बन्ध में कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है, उसके केसिज बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उनका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। इन सब बातों को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल कमेटी ने दिसम्बर मास में कुछ प्रोपोजल सरकार के सामने रखे थे।

वे प्रोपोजल्ज चार महीनों से वैसे ही पड़ी हुई हैं, कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई है। अगर उन प्रोपोजल्ज की तरफ तवज्जह दी जाए तो इस बात का बहुत बड़ा इमकान है कि इनकम-टैक्स के केसिज का जल्दी से जल्दी तसफिया हो जाए और इनकम-टैक्स की जो वसूली है वह भी अच्छी मात्रा में आगे बढ़ती चली जाए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि जो स्कीम डिपार्टमेंटल कमेटी ने भेजी है और जो अभी कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है, उसको देखें और जल्दी से जल्दी उसको अमल मे लाने का प्रयत्न करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**Mr. Speaker:** Shri Somani.

**Shri Raghunath Singh** (Varanasi): I also want to catch your eye.

**Mr. Speaker:** Shri Somani has caught my eye in preference to the hon. Member.

**Shri D. C. Sharma** (Gurdaspur): Have I caught your eye, Sir?

**Mr. Speaker:** I do not know.

I shall try to give opportunity to all hon. Members.

**12.32 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

**Shri Somani** (Dausa): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like at the very outset to congratulate the hon. Finance Minister on the cheerful picture which he has been able to present about our national economy in his budget statement. There are certain good and healthy features about our economy to which special attention may be drawn, that is, the stability of our price structure, the buoyancy of our revenues, the increase in our agricultural and industrial production and the favourable prospects of receiving the necessary external aid from friendly countries for the success of the Third Five Year Plan.

There is no doubt that dynamic progress is being made in the various sectors of our economy and we are well on the road to an accelerated growth of development, and if only our Government will take timely and effective measures to tackle certain bottlenecks, we will in the course of the next few years be certainly able to take our economy to the take-off stage.

At the same time, the hon. Finance Minister has given real scope for genuine apprehensions about a very substantial further dose of taxation in the new budget and it is really that genuine apprehension of additional taxation load that causes serious concern to everybody. There is no doubt about the fact that the taxation, both direct and indirect, has reached a point where before any additional dose is imposed, it would be worthwhile to explore the various other avenues by which it might be possible to go ahead with the fulfilment of our Plan.

I would like first to draw the attention of the Finance Minister to the consistent underestimates of our revenues being done year by year. In 1959-60, the surplus in revenues over the estimated figure was Rs. 90·33 crores; in 1960-61, it was Rs. 52.14 crores and in this year, 1961-62, it is Rs. 61.16 crores. In other words, this surplus in revenue of about Rs. 60 crores is

almost a 100 per cent increase over the amount of additional taxes which the Finance Minister had imposed on the assessment of certain revenues. It is really very desirable that in our future budgeting the assessment of our revenues is made on a more realistic and practical basis.

Apart from this, there is a large scope for augmenting our resources by increased borrowings, both internal and external. It is due, as a matter of fact, to the shortfall in our borrowing programme that the Finance Minister has been faced with an overall deficit of the magnitude which he has indicated. It is therefore only appropriate that sustained and determined efforts should be made to increase our resources by greater resort to borrowings.

Even in the field of small savings, there is a vast scope to increase the resources from the countryside. While it is compartively easy to raise the resources by increasing taxation, it does require a lot of consistent, persistent and determined effort to increase the resources by small savings and by various other ways of borrowings. It is, therefore, desirable that the borrowings programme should be intensified and all necessary measures in this connection taken.

Then the question of consistent increase in civil expenditure has always caused a great concern to this House, and attention has from time to time been drawn to the need to ensure that all our resources are utilised usefully. There is no doubt that if determined and proper efforts are made to generate savings from this sector, that is, through avoidance of wasteful expenditure, and also various other ways of bringing about economies in the programme of implementation of our huge development projects, it should be possible to earmark some portion of the resources to be generated by these savings and economies which are absolutely practicable, to fill up the gap.

Apart from this, in the programme of developmental expenditure of the magnitude of Rs. 1,446 crores which he has planned for the second year of the Third Plan, it does seem practical to contemplate that there is bound to be some saving in the implementation of this programme. There is bound to be shortfalls in developmental expenditure due to various reasons over which Government have no control. It can, therefore, be safely concluded that this provision of Rs. 1,446 crores will also leave certain savings at the end of the next budgeting period.

Then attention has rightly been drawn in the *Economic Survey* to the need for making every possible effort to see that our huge investments in the public sector projects generate savings to an extent sufficient to enable those savings to be further invested in the expansion or in new projects of the public sector. This is another aspect which should receive the very urgent attention of the Planning Commission and Government. I am suggesting all these measures with this end in view, that instead of taking the direct step of imposing additional taxation, it will be quite appropriate in view of the present economic situation to explore all other possible avenues to find the resources necessary for the implementation of the Third Five Year Plan.

Having made these observations about the present economic situation, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to certain disquieting features and certain serious bottlenecks with which our economy is faced. I would invite his attention to the very interesting and illuminating articles written by Shri G. D. Birla recently about the Third Five Year Plan. Shri Birla is well known for his pro-Government and constructive approach of robust optimism, and yet a man of his calibre and stature with all his constructive and optimistic approach, has expressed certain genuine apprehensions and taken a gloomy view of the prospects of the success of the Third Plan. He has

[Shri Somani]

drawn attention to certain bottlenecks.

He has used such strong words suggesting that nothing moves in Delhi and that there does not seem to be any appreciation of the urgency in the various government departmnts to go ahead with the implementation of the gigantic programme of our economic development. That is not something which is coming from him alone.

Complaints have been made and attention has been drawn by various quarters to the serious loss which is caused to our national economy by the administrative delays and administrative inefficiency. I will give a few instances as to how certain avoidable losses have been suffered by us simply because of the fact that our Government has not been fully alive to the necessity of dealing with the vast development economy.

Let us first take the question of coal. The other day, the hon. Minister for Steel, Fuel and Mines told us that the question of switching of certain industries over to oil is under the consideration of government. So far as this difficulty of coal supply in various industrial centres is concerned, I think the hon. Finance Minister will admit that this is not a new phenomenon. I think it is almost 18 months since the various industrial centres have been experiencing acute shortage of coal and the situation, instead of improving, is deteriorating day by day. The latest revision of coal allocation made by Government has created genuine apprehensions in the mind of the various industries as to how adversely they will be affected in their production.

This question of switching over from coal to fuel oil is an asbolutely simple one. Government have simply to ensure that the prices of fuel oil will be competitive with that of coal. It is quite obvious that Government will have to sacrifice part of their revenue by way of excise duties on this fuel oil. But, I think the national economy will be losing much more than this loss of excise duty if Government does not take timely measures to make oil prices competitive with coal. The loss of production affects the national economy in so many ways like loss of employment etc. The implication of the loss of production is felt in various other ways. It is, therefore, high time that the Finance Ministry, which has got the main responsibility of making the oil prices competitive with coal, tackles this problem on the basis of the priority which it deserves.

It is true that such questions are being studied by the Planning Commission and by the various departments or Ministries and they take their own time in coming to conclusions. But these have to be tackled according to the priorities which they deserve and in a realistic and urgent manner than what Government have done so far.

The question of coal production itself deserves to be tackle in a much more effective manner. The other day, from the spokesman of the coal industry itself we found that they are genuinely apprehensive of the achievement of the further increased targets allowed to the private sector and the public sector in the matter of coal production. There is shortage of power; there is shortage of transport and the policy of fixing coal prices is absolutely unrealistic. All these have created such a situation that those who are in the coal industry are definitely apprehensive of the serious crisis being further aggravated by the loss of production in coal or by the coal industry not being able to fulfill the targets that have been allotted to them.

All these matters have got to be tackled effectively if further loss of production has to be arrested.

We have been told that there has already been a slowing down of industrial production. Industrial production in 1961 showed an increase of only about 7 or 8 per cent. compared to 12 per cent. which was the figures for 1960. That is something of which

serious notice should be taken by the Planners and the government departments concerned; because, while we are thinking in terms of accelerating the pace of progress, the slowing down of industrial production, certainly, cannot but be viewed with grave concern by everybody.

I will come to the question of power. The other day, hon. Member, Shri Banerjee was complaining that the U.P. Government have allotted substantial power from the Rihand Dam to Birlas and have deprived a number of small-scale and medium-scale industries of power from that source. I hold no brief either for the U.P. Government or for the Birlas who have sponsored the aluminium project. But, I would like to inform the House that the Birlas have proposed the generation of their own power; and they are prepared not only to arrange power for their own aluminium units but they are also prepared to generate extra power to make it available to others who may be in need of power in those areas. What is more significant is that the Birlas have made an offer they will not require any foreign exchange for the development of that power resource. They have made arrangements to secure the power plant from rupee sources. Their proposal is pending before Government for a very considerable period.

The other day, in the Press Conference, the hon. Prime Minister said that the policy in regard to the establishment of power projects by the private sector is clear and it is not against the Industrial Policy Resolution to allow the private sector projects to be established for the development of power. And yet, in a case, where obviously there is strong criticism of the Birlas getting a major portion of the Rihand power for the aluminium plant, their proposal for generating their own power has been hanging fire in the Planning Commission and the various Ministries for a long time.

I am not making any special plea for any individual case. What I am trying to do is to draw the attention of the Finance Minister to this lack of urgency on the part of the various government departments to tackle the various issues in a pragmatic manner, of which we have been assured time and again. I also realise the complexity and the complicated nature of the decisions which our officers have to take on the various issues with which they are confronted. But national economic interest is supreme and nothing should be allowed to drag on which will mean avoidable loss.

About power I have to make some other submissions also. The Third Plan provides for an increase in the installed generating capacity of 123 per cent. over the Second Plan. This, however, is wholly inadequate. During the period 1948-55, the relationship between power consumption and industrial growth was such that for every 10 point rise in the increase of production, the increase in power consumption was of the order of 18 points. For the period 1955-61, the corresponding figures are that for a ten point rise in industrial production, the increase of power consumption was 23 points. On this same basis, for a 70 point increase in industrial production that is envisaged in the third Five Year Plan, the increase in power consumption should be of the order of 163 and not 128 as stated in the third Plan. 123 per cent. represents the installed generating capacity whereas 163 represents the actual requirements, which means that the installed capacity should be more than 163 in order to allow for some idle capacity to meet the requirements of emergencies. Obviously, the allocation for power has got to be substantially increase if we are to really make for sufficient power for the dynamic growth in the various sectors of our economy.

We have been assured of priority being given to the development of power and transport resources, both in the *Economic Survey* as well as in the Finance Minister's speech. But, as I was submitting, there are short-

[Shri Somani]

term and long-term solutions of this problem. The short-term solutions are to enable the various industries in need of coal and power to make such arrangements as may be feasible under the circumstances. The long-term solution is to increase the allocations for the development of these key sector projects to an extent which will take care of the needs of the situation.

I would like now to say something about the question of export promotion. The Mudaliar committee had submitted its comprehensive report to the Government recently and it contains very constructive and interesting suggestions for the expansion of our export trade. But may I submit that here again some of the very important suggestions which they have made are not new. I may refer to the question of giving incentives in the form of income-tax relief for the promotion of exports. I do not say that the industries as such have no responsibility to foster and promote export trade. Certainly they must be asked to make all possible sacrifices and efforts and do their best in the field of exports. But certain constructive suggestions made by the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry and various other bodies during the last few years to the Finance Ministry have had absolutely no response so far. Even in the very progressive and industrially advanced countries like Japan, Germany, France, etc. this scheme of incentives has worked wonders and there is no reason why the Government should feel shy of introducing certain bold and imaginative measures instead of taking piecemeal measures.

Another important question about export trade is the price structure. Our various manufactured goods are simply priced out in the international markets. That is due to the rigid price structure both due to the various steps the Government take and also some reasons beyond the control of the Government. Therefore, our industries are not in a position to produce goods of proper quality at an internationally competitive price and it is here that modernisation and rationalisation can help. It is a long term problem and the Planning Commission and the Government departmets must give their thought to this question of how to make our industries modernised, rationalised and better equipped in order that they may achieve the targets for the Third Plan exports. Unless that is done we may not be able to fulfil the targets for exports. Unless we increase our exports it is obvious that our programme of economic development is bound to suffer. At a time when the Government is seized of the question and when the Mudaliar Committee report is being examined, Government should take measures of short-term and long-term character to give great fillip to our export trade.

I would then like to refer to the situation in the textile industry. This year, again cotton crop is expected to be much less than normal—in the neighbourhood of four million bales. Unless necessary foreign exchange is made available or Government negotiates imports of foreign cotton on any other basis, the industry is threatened with a situation where again there will be shortage of cloth, loss of employment and various other adverse repurcussions. Representations have been made for the need to import extra cotton to keep the industry working until the new season starts. I hope that something is being done to ensure the availability of adequate raw material for the proper functioning of the textile industry.

We are in the midst of dynamic development in various sectors of our economy and the private sector is making its due contribution. Even this morning our respected Prime Minister in his inspiring address to the Federation did recognise the usefulness of the mixed economy under which we are progressing and how essential it is to

continue to allow the private enterprise to function smoothly subject of course to our programmes and policies as laid down in our plans. The potentialities of development of the private sector should not be overlooked. The history of the last decade of planned development clearly indicates that the private sector has overfulfilled its targets and it is today in a position to make a much more effective and dynamic contribution to the achievement of the planned targets allotted to it. It is incorrect to say that the private sector has in any way been criticising the functioning of the public sector. We all welcome the growth and development of the public sector which is necessary for the proper growth of even the private sector; there is absolutely no conflict between the two. But the requirements of the private sector are often ignored but so far as the financial resources of the public sector are concerned, due provision is made by various ways and ultimately by resorting to fresh taxation. But no realistic appraisal of the requirements of the private sector for foreign exchange or internal resources has been made by the Planning Commission and the private sector has been left to find its own resources. Due to the stability of our Government and various other favourable policies in the economic field pursued by our Government and also due to the stability in our economy, generated by the very wise way in which our present Finance Minister has handled the whole situation, there is such a tempo of growth in the country as well as a fund of goodwill in the international market that it will be worthwhile to give proper and wider opportunities to the private sector to avail of this favourable situation and to make their due contribution in this programme of building a new India.

**Mr. Deputy-Speaker:** Now every hon. Member shall conclude his remarks within twenty minutes as I find that the list here is swelling every minute.

**Shri N. R. Muniswamy** (Vellore): Sir, the interim Budget presented by the hon. Finance Minister reveals certain interesting features which deserve some comments from the hon. Members of Parliament. Some of these features are very illuminating in the sense that the reasons assigned by the hon. Finance Minister seem to carry conviction on the face of them.

Before dealing with them I shall make a few observations about the general trends in the economy. The Finance Minister has claimed that he has checked the rising prices. To some extent they have been checked because of the rise in the production in the industrial and agricultural sectors. One thing which causes some concern is that there is an over-all deficit for this year 1961-62 to the extent of about Rs. 121 crores. That indicates that we have to somehow or other mobilise our resources with a view to see that the Plan is properly achieved. If the resources are not properly mobilised it would lead to difficulties and we may not be able to attain the targets laid in the Plan.

**13 hrs.**

The Finance Minister has picked up courage for converting the deficit into a revenue surplus. In this connection I would like to read paragraph 17 of his Budget Speech which says:

> "The budget year estimated the revenue receipts at Rs. 1,017.95 crores and expenditure met from revenue at Rs. 1,023.52 crores. On current trends, the revenue receipts are likely to go up to Rs. 1,079.11 crores and the expenditure to Rs. 1,045.15 crores, with the result that the budgeted deficit of Rs. 5·57 crores will be converted into a revenue surplus of Rs. 33·96 crores."

The reason for this is stated by him in the next paragraph, that is paragraph 18.

> "The improvement in revenue receipts is mainly due to better collections under Customs, Union Excise Duties and Corporation Tax and Income-tax. Larger

[Shri N. R. Muniswamy]

imports of machinery and mineral oils and imposition of countervailing duties on the latter account for an increase of Rs. 9.96 crores under Customs. Union Excises are expected to be more by Rs. 38.32 crores, following the general improvement in production and clearances, increase in the duty on mineral oils and better realisations from new excises. With the rapid growth of business and industry the revenue from Income-tax including Corporation Tax is likely to go up by Rs. 28 crores. These improvements, however, will be partly counterbalanced by the increase of Rs. 13.45 crores in the States' share of Income-tax and Estate Duty."

What he means to say is that the unanticipated income from these sources account for the conversion of the apparent deficit into surplus. The increase has been attributed to the income from the customs and Union excise. I cannot understand how receipts under Customs could not be anticipated because we have a programme of imports of machinery and mineral oil which is in pursuance of a policy decision. Everybody is aware that we are going to import machinery of a particular value and it is very easy to know what customs duty would be realised on it. The increase is also attributed to income from excise. Income under this head also could easily be calculated. It is not as if machinery and mineral oil could be smuggled into the country from anywhere in the world. Everybody knows how much is likely to come. This means that the apparent conversion of this deficit into a surplus is only a mathematical or arithmetical metamorphosis. Otherwise this conversion of the deficit into a surplus cannot be accounted for. The other possibility is that budgeting has not been done on a scientific or understandable basis.

The forecast for 1962-63 is on the same basis as the existing taxation and the Finance Minister expects a deficit of Rs. 63.46 crores. One of the papers, the *Hindustan Times* or the *Indian Express*, had mentioned that the practice adopted by the Finance Ministers is always to take the notional deficit as a ground for bringing new taxes. This is a very easy way of shifting a debit into a credit, but the inflationary effect of it is likely to be great and is bound to affect our economy, bringing in its wake adverse effects on millions of our people. The Finance Minister has honestly stated that unless our resources are increased, we may not be in a position to stabilise our economy, and that is the main reason why he resorts to deficit financing. All the same the effect that it has on our economy cannot be ignored. It is bound to dislocate our general life.

In my view in a developing country like ours, saving with a view to investment is very essential. This is a better way of raising resources than through new taxes. Our national income is rising and we should see that the structure of our taxation is made flexible so that money in the hands of people is siphoned into the coffers of Government. Instead of resorting to fresh taxation, the hon. the Finance Minister should encourage saving among people, which they should be encouraged to invest. With this end in view public cooperation should be enlisted. People should be made to understand that savings invested with Government go for the benefit of the people.

At present there is a suspicion among the people that there is large infructuous and avoidable expenditure on the part of Government. People are not able to know whether the expenditure incurred on different items is for their benefit or not. They feel that some of the expenditure of Government is in unprofitable directions. We are all aware of the severe criticism levelled against infructuous

expenditure in the various P.A.C. reports. Members of Parliament and the House should be made aware of the corrective measures taken by Government.

In Annexure IX of the *Explanatory Memorandum* we find a list of 559 important new items of expenditure costing Rs. 5 lakhs and above, involving a total expenditure of 12,28,36,19 lakhs of rupees. What causes us concern is that such expenditure is likely to gather momentum in the years to come. Some of them may even relate to non-Plan expenditure. We must be in a position to satisfy ourselves that these items of expenditure are properly screened and scrutinised.

[SHRI MULCHAND DUBE *in the Chair*]

In this connection, we have been agitating for a long time that the Standing Finance Committee which was functioning some years back should be revived. It had been abolished because there had been some sort of an adverse comment that the existence of such a Committee was not necessary. It is better that we now take up some courage and revive the Standing Finance Committee. That will keep each of these items before its eyes, namely, the items which are included in the budget estimate. If there is a Standing Finance Committee, it will certainly go through all the items and would certify whether each item is worth including in the budget estimate or not. Therefore, it is better we revive the Standing Finance Committee.

Coming to the expenditure on defence, there is a net increase of Rs. 38 crores. I quite appreciate it. We have to spend this amount for the maintenance of our territorial integrity and safety of our country in the context of the present world tension and the attitude of some of our neighbouring countries which is not friendly. I quite appreciate it. But, at the same time, year after year, we find in the audit reports some sort of criticism levelled against the infructuous and purposeless expenditure incurred by defence. Therefore, I would say that the expenditure which is of a greater magnitude deserves to be checked at the proper time. The working of the defence, ordnance factories, where expenditure on a large scale is incurred on educational orders and on new experiments, some of which are half-baked ones, happens to be the target of criticism in the audit reports. I would only add that when we are in the crisis of development, the Finance Ministry and the Defence Ministry should sit together and see that there is no room for any avoidable expenditure and they must assure us that there would be no avoidable expenditure at all.

There is one other item which I would like to bring to the notice of the House. That item is termed as loan from Kuwait Government. I may be permitted to read that portion, because it is written in a separate paragraph at page 190 of the Explanatory Memorandum. It reads as follows:

> "Special Indian notes and Indian coins which were in circulation in Kuwait ceased to be legal tender with effect from 1st April, 1961, and a new local currency 'Dinar' introduced from that date replaced them. According to the agreement signed on 20th March, 1961 with the Government of Kuwait the value of all Indian Currency exchanged by the Government of Kuwait and returned to the Reserve Bank of India, has been transferred to the Government of India and the amount so transferred, treated as a loan from the Government of Kuwait to the Government of India repayable in Sterling. This loan amounting to Rs. 34.19 crores is to be repaid in eleven annual instalments, beginning from the 1st July, 1961. Interest at the rate of 4½ per cent is payable on the outstanding balance from time to time."

What I say is this. This sum, which involves Rs. 34.19 crores, has been

[Shri N. R. Muniswamy]

agreed to be paid by the Government of India to the Kuwait Government, because we have withdrawn all the currency notes which were in circulation in the Middle East. We have adopted certain methods to see that there should be no smuggling and that our own currency with a different mark and dimension is introduced. In spite of that, I find it was not successful, and they have rightly withdrawn their circulation. But what I mean to suggest is that this agreement has not been placed before this House for its approval, nor has it been placed in this House for the Members to go through. Such an agreement which is entered into, involving such a huge sum, has to be placed before this House and the sanction of the House obtained. I find—I am subject to correction—that no such steps have been taken. I wish that this situation ought not to be repeated next time.

The *Economic Survey* which has been issued to us along with the budget papers and the Explanatory Memorandum discloses clearly that there is not much room or there is no room for complacency and that, on the other hand, there is room for concern. The internal borrowings during the past few years were not up to the mark. The position of the foreign exchange reserves just at the beginning of the second Five Year Plan was very happy. It was about Rs. 750 crores. By the end of the second Five Year Plan, it had dwindled to Rs. 156 crores or so. The position, therefore, has worsened, in spite of the reduction in imports and increase in exports because of what the Finance Minister has rightly described as structural changes on our invisibles. That is what he says. The burden of foreign debts is already growing and our earning on the foreign investments has almost been nil. Therefore, there are certain major problems which will be created in the next four years by certain internal factors. These factors, to which I request the Government to give some attention, are certain scarcities of the basic aspects of the industry. The *Economic Survey* makes mention of them in a passing way, saying that the apparent shortage of coal, power, transport and certain varieties of steel is only a temporary one, and there is bound to be some bright future. But in the developing economy, it is not possible for us to belittle this present shortage of the basic materials. The industrial revolution which is now taking place here will be jeopardised if we are not able to tackle these phoblems in a dynamic way.

From the reports, I find that industrial production has dwindled from 12 per cent to 7 per cent, from 1960-61 to 1961-62, and that the national income also is getting less. The investment is large and the return, compared to the investment during the course of the five years, is less than expected. Taking into consideration the entire Five Year Plan, the total outlay that is made for the first two years of the third Plan is Rs. 2,500 crores. A balance of Rs. 5,000 crores is left, and that balance has to be made up in the next three years. Therefore, we have to step up our production, keeping these factors in view. In the context of the shortage in power, coal transport and steel, I am afraid whether we will be able to step up the production or to meet this challenge. I want these problems to be tackled vigorously.

Several of the public sectors are still in the investment stage and are quite far from yielding returns on their outlay. The budget memorandum shows that out of about 68 concerns in the public sector, in all of which about Rs. 605 crores have been invested up to March, 1961, barring about a dozen enterprises, all the rest are expected to yield only a very meagre profit in the year 1962-63. Only about a dozen concerns might possibly give us a profit. About the rest of the concerns, the projects are

not likely to come in soon and result in profits in the near future or even in 1963-64. Against a total of investment of about Rs. 880 crores in all, except one or two important concerns as the STC and the Oil India Limited, all the others do not promise to give us much. I find from the memorandum that the total return that we get from the investment is about Rs. 3.12 crores. If the Oil India Limited and the STC are eliminated from the list, the return would be about Rs. 2 crores only from all the rest, when compared to the investment. Therefore, it looks as though something is rather wrong somewhere. We are paying about Rs. 30 crores annually by way of interest alone. How are we to meet the situation? As a matter of fact we get an yield of only Rs. 2 crores to Rs. 3 crores, even allowing for the initial incubation period for the industrial concerns. All industries, to start with, have of course some teething trouble. All the same, there is a certain feeling among the people that proper steps have not been taken to see that these concerns are made more remunerative. I only wish that, with the dynamism of the Finance Minister, he will whip up these concerns to see that proper profits are earned, commensurate with the investments made.

The Finance Minister has further stated that we have to take some courage to enlarge the scale of deficit financing. By so doing, the inflationary pressure will not be checked; it will add to the existing price level. Unfortunately, there seems to be a belief that though initially there may be some trouble, finally it will be settled as time passes. I do not think that it will happen like that if you allow things to drift in that way.

On the whole, the budget that has been presented has commended itself to many of our friends here. All the same, I can only ask the Finance Minister to see that whatever methods are being adopted, they must be to the satisfaction of the people. As a matter of fact, this budget on the eve of the election only keeps the tempo as it was and it has thrown a grim picture that we have to resort to taxation if we really want to see that our country progresses, along with other countries. Therefore, the Finance Minister is not so optimistic and the budget shows that we have to sacrifice a lot for the sake of the country. I do not mean to say that we have to reduce our consumption. Reducing consumption is not the method, which should be adopted. But all the same, a certain amount of sacrifice has to be made by the people if we want to co-operate with the country in its progress.

With these observations, I commend the budget for the acceptance of the House.

**श्री पहाड़िया** (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने वित्त मंत्री के भाषण और बजट पर जो बातें कहीं, उनको मैंने बहुत गौर से सुना । बहुत सी बातें मैंने भी अपने भाषण में, जो कि मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर दिया था कही थीं । लेकिन कुछ नई बातें जो यहां पर कही गईं उनके बारे में मैं प्रकाश डालना नहीं चाहता, मैं केवल वित्त मंत्री जी को उनके भाषण के लिये और उन्होंने जो संतुलित बजट हमारे सामने पेश किया, उसके लिये बधाई देना चाहता हूं ।

वित्त मंत्री जी जब से वित्त मंत्री बने हैं, उनके बारे में तरह-तरह की अफवाहें और भ्रांतियां हम लोग सुनते रहे हैं । एक बड़े आदमी का भ्रांतिमय होना मेरी राय में अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार भ्रांतियों के केवल भ्रांतियां बने रहने से भी

[श्री पाड़िया]

मामला गड़बड़ी में पड़ जाता है । जहां तक मैं समझ पाया हूं, उन्होंने अब तक जो बजट पेश किये हैं, उनके हिसाब से हमको साफ इंडिकेशन मिलता है कि हमारा मुल्क समाजवाद की ओर बढ़ रहा है । यह बात सही है कि मुल्क में बढ़ते हुए टैक्स और बेकारी गरीबों की कमर तोड़ देते हैं । जब एक तरफ हम देखते हैं कि मुल्क के अन्दर बड़े-बड़े कल और कारखाने खुल रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं, देश के अन्दर खेती के विकास के लिये नहरों का और सिंचाई का इन्तजाम हो रहा है, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिनसे कि होते हुए फायदे हमको नुकसान नजर आने लगते हैं । मिसाल के तौर पर एक बड़ा भारी बांध या नहर आपने बनाई, उससे आपको लाखों क्या करोड़ों रुपये का लाभ मिला क्योंकि उससे बहुत सी जमीन की सिंचाई होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट है कि उस इलाके के गांवों में रहने वाले लोग और आबादी कभी-कभी उस के रास्ते में आ जाते हैं, जिससे कि उनको वहां से उठाना पड़ता है । मानी हुई बात है कि उससे उनको नुकसान हो जाता है । इसलिये इस बात का भी ध्यान हमारे वित्त मंत्री जी रखें कि जब भी मुल्क में एक तरफ बड़ी-बड़ी योजनायें बनें और उन योजनाओं के जरिये से लोगों को लाभ पहुंचे और दूसरी तरफ अगर समाज के किसी खास तबके को उससे कुछ नुकसान हो तो उनको भी फायदा पहुंचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

यह बात मैंने खास तौर से इसलिये कही कि राष्ट्रपति जी के भाषण पर एक तरफ तो हमारे माननीय सदस्य और बुजुर्ग पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस सदन में यह आरोप लगाया कि पिछड़ी जातियों ने खास तौर पर कांग्रेस को वोट नहीं दिया । उन में से भी, उन्होंने कहा, खास तौर से हरिजनों, गैर चमारों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया । इस बात को मैंने बहुत गौर से सुना । मैंने सोचा कि मैं उसी समय उनको इस बात को समझा दूं लेकिन मैंने हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा । दूसरी तरफ मैंने भाषण सुना अपने महान नेता पंडित जवाहरलाल जी का, जो कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ही नहीं, बल्कि प्यारे नेता भी हैं । उन्होंने कहा कि हम हरिजनों को केवल इसलिय नौकरी या किसी दूसरे रूप में अधिक सुविधायें नहीं दे सकते कि वे हरिजन हैं । उन्होंने कहा कि योग्यता हमारा आधार होना चाहिये । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन इन दोनों भाषणों को सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक रस्साकशी होती है । मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। कहा गया कि चूंकि हरिजनों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया इसलिये सरकार का साथ नहीं दिया क्योंकि सरकार कांग्रेस की है । सरकार ने हरिजनों की भलाई के लिये जो-जो काम किये हैं वह छिपे हुए नहीं हैं । उनके लिये आज मैं भारत सरकार को, वित्त मंत्री जी को और दूसरे राज्यों की सरकारों को धन्यवाद देता हूं । लेकिन जब सरकार इतना कर रही है हरिजनों के लिये फिर हरिजन सरकार का साथ नहीं देते, तो इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ जरूर है, और उसकी झलक हमें मिलती है पंडित जी के भाषण में से । पंडित जी ने कहा कि हम हरिजनों को केवल इसलिये नहीं बढ़ा सकते कि वे हरिजन हैं, बल्कि योग्यता को सामने रक्खेंगे । मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह बात गलत है, लेकिन मैं पंडित जी से पूछना चाहूंगा कि योग्यता का आधार क्या है ? आम चुनावों में योग्यता का आधार मेजारिटी से लगा लिया गया है । अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो जिन लोगों ने पिछले आम चुनावों में वोट दिया उन्होंने, हम सब ने, जनता ने देश के योग्य उम्मीदवारों को भी छोड़ दिया,

उनकी समझ में जो आदमी आया उसको आगे कर दिया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आखिर योग्यता का आधार क्या है ? योग्यता का आधार अकेडेमिक या जनता के हित में जान दे दे वह है । अगर दोनों का मिक्सचर हो जाये तो बहुत अच्छी बात है । इसलिये मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये जो बात हम कहें उसे स्पष्ट रक्खा जाना चाहिये । पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि गैर चमारों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो उसका कारण यह है जैसी कि मैंने मिसाल दी, कि कुछ कामों से बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा लेकिन एक तबके को नुकसान हो गया, उसी तरह से हरिजनों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी तादाद बहुत थोड़ी है, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनकी तरफ हम ध्य न नहीं देते हैं, न हमारी सरकार के कर्मचारी ही देते हैं । मेरा निवेदन है कि यह नजला हरिजनों पर उतारा न जाये हरिजनों के अन्दर अनेक जातियां हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, अगर उन जातियों को नेगलेक्ट करके किसी जाति विशेष को लाभ पहुंचाया जाये तो उसका साफ नतीजा यह निकलता है कि जो दूसरी जातियां हैं जिनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है और जिनके नाम पर दूसरों को फायदा मिल रहा है, वे नाराज होती हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपका बजट बने तो इस बात का ध्यान रक्खा जाये कि इस देश के अन्दर रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वे हरिजन हों चाहे गैर हरिजन हों, हरिजनों में भी चमार हों या गर चमार हों, सबको समान अवसर मिलना चाहिये । यह मामला लोक सभा पर छोड़ देना चाहिये कि वह कितना रुपया दे सकती है । इससे मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जो कहते हैं कि हरिजनों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और पंडित जी को भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हम हरिजनों को केवल इसलिये नौकरी नहीं देंगे कि वे हरिजन हैं । जो योग्यता की बात उन्होंने कही है उस को सचमुच मैं भी मानता हूं कि व हरिजनो को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ायेंगे ताकि जो लाभ उनको मिलना चाहिये इस सरकार के अन्दर, प्रजातन्त्र के अन्दर, वह उसे उठा सकें ।

इसके साथ ही मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मुल्क के अन्दर जहां खेती के उत्पादन में वृद्धि हुई वहां उसके साथ ही साथ भूखों की भी वृद्धि हुई । इस तरह से हमारी बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है । इसका कारण क्या है ? इसका सब से मुख्य कारण यह है कि हमारे देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है । जब तक इस आबादी की वृद्धि को रोकने के लिय कोई कदम नहीं उठाया जायेगा तब तक आप चाहे जितना भी पैसा योजनाओ में लगायें, चाहे जितनी बड़ी-बड़ी योजनायें बनायें, चाहे जितने बड़े-बड़ बांध बनाते चले जायें उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी तरफ हिन्दुस्तान की जो अवाम खाने के लिये अनाज मांगती है, पहनने के लिय कपड़ा मांगती है और रहने के लिये मकान मांगती है, उनकी वृद्धि होती चली जायेगी जब तक उसकी वृद्धि होती चली जायेगी तब तक आप इस दौड़ में पीछे रहेंगे । देश के अन्दर जो बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो सके शहरों और गांवो में, दोनों जगह, इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने का उपाय किया जाना चाहिये । जब आबादी रुक सकेगी तो यह निश्चित है कि काम चाहने वालों की संख्या कम होगी और जब काम चाहने वालों की लंख्या कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जा सकेगा और तब यह शिकायत, कि देश में गरीबी और बेकारी

[श्री पहाड़िया]

बढ़ रही है, रहने वाली नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिये कोई उपाय खोजना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं । वह यह कि जब हमने हिन्दुस्तान में समाजवाद का नारा लगाया तो उसको सफल बनाने के लिये हमने टैक्स लगाए । टैक्स लगाना स्वाभाविक है । कहा जाता है कि जो टैक्स लगते हैं उनका अधिक भाग गरीबों पर ही पड़ता है । लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनका भार गरीब और अमीर सभी पर पड़ता है । वर्तमान अवस्था में चाहे वह प्रत्यक्ष टैक्स हो या अप्रत्यक्ष टैक्स हो, उनका भार करदाताओं पर पड़ता है और करदाता हिन्दुस्तान में रहने वाले गरीब उपभोक्ता हैं । और वह कहां से इस टैक्स का इन्तजाम करे इस बात की परेशानी में पड़ जाता है । उसकी आमदनी बहुत थोड़ी होती है और टैक्स बराबर बढ़ते चले जाते हैं । उनका भार उस पर पड़ता है ।

कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रत्यक्ष कर लगायें जायें तो गरीबों पर कम भार पड़ेगा । मैं भी इस बात को मानता हूं क्योंकि प्रत्यक्ष कर का भार पैसे वालों पर ही पड़ेगा । लेकिन उस टैक्स को लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि जिन लोगों पर आप वह टैक्स लगाएं वे उस टैक्स को उन लोगों से वसूल करके आपको दें जिन पर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते । मिसाल के तौर पर आपने पिछले बार सफेद मिट्टी के तेल पर टैक्स लगाया, जो कि बढ़िया किस्म का होता है लेकिन हमने देखा कि शहरों में और गांवों में हर किस्म के मिट्टी के तेल पर चाहे वह पीला हो या घटिया किस्म का हो, दुकानदारों ने टैक्स वसूल कर दिया । इसी तरह से चाहे आपने टैक्स लगाया सिगरेट पर या अच्छी तम्बाकू पर लेकिन गांवों में हमने देखा कि गांवों में काम आने वाली तम्बाकू पर भी वह टैक्स वसूल कर लिया गया । आपके सरकारी कर्मचारियों ने वह टैक्स वसूल नहीं किया लेकिन दुकानदारों ने गरीब जनता से वह टैक्स वसूल कर लिया । तो इस बात का इन्तिजाम होना चाहिये कि जो भी आप टक्स लगायें वह उन्हीं से वसूल किया जाय जिन पर आपने टैक्स लगाया है । ऐसा न हो कि वे लोग दूसरे लोगों से—जिन पर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते—वह टैक्स वसूल करके आपको पे करें । इस इन्तजाम को करने के लिये अच्छे कर्मचारी होने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार न हो ।

पिछले आम चुनावों के समय राजस्थान में इस बात की बड़ी चर्चा रही और स्वतंत्र पार्टी के नेता लोगों ने—जो कि वास्तव में कोई नेता नहीं हैं लेकिन अपने को नेता कहते हैं—खास तौर से राजा महाराजाओं ने इस बात को कहा कि देखिए कांग्रेस सरकार बराबर अपने टैक्स बढ़ाती चली जा रही है और इसके साथ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । यह बात एक मानी में सही है । हम देखते हैं कि गांवो में रहने वाले लोगों की आमदनी बहुत थोड़ी है, चाहे वह पटवारी हो या स्कूल मास्टर हो । वह कहां से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये पैसा लावें । कहां से उनके लिए उचित भोजन वस्त्र आदि का प्रबन्ध करें । उनकी आमदनी बहुत कम होती है और बढ़ती नहीं है । और आज जमाना तरक्की करना चाहता है । हर को अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दिलाना चाहता है। अच्छा मकान बनाना चाहता है । जिसकी आमदनी ज्यादा है वह यह कर सकता है लेकिन जिसकी आमदनी कम है वह भी पीछे नहीं रहना चाहता । और इस काम को करने के लिये वे लोग निश्चित रूप से कुछ

रिश्वत लेते हैं। इस बात की चर्चा राजस्थान में ज्यादा हुई। और यह कहा गया कि कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं उन लोगो से जिन्होंने यह कहा पूछना चाहता हूं कि जब उनका राज्य था क्या उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। यह ठीक है कि उस समय इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन उस समय इसको भेंट, बेगार आदि अनेको नामों से पुकारा जाता था, जिन नामों को अगर राजस्थानी भाषा में यहां बतलाऊं तो आप समझेंगे भी नहीं। तो जनता को समझाने के लिए हम क्या करें। मैं समझता हूं कि टैक्स लगाने का एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए जिससे लोगों को पता हो कि कौनसा टैक्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है और उनको गलत शिकायत करने का मौका न हो। जनता को ठीक प्रकार से पता नहीं चलता कि कौनसा टैक्स कौन लगाता है। यह पता तब तक नहीं चल सकता जब तक कि जनता शिक्षित न हो। इसलिए शिक्षा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। गांवों में स्कूल खुले हैं लेकिन और खुलने चाहिए। हमारे जो विकास कार्य हो रहे हैं और गांवों में जो स्कूल और अस्पताल आदि खोले जाते हैं और देश जो तरक्की कर रहा है उसका ठीक प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने प्रचार विभाग को एक ऐसी योजना बना कर दें कि जिससे इन चीजो का गांवों में प्रचार किया जाए कि सरकार इन कामों को कर रही है, राजे महाराजे नहीं कर रहे। अभी भी गांवों में लोग यह समझते हैं कि राजे महाराजों का राज है। और ऐसा प्रचार करने के लिए कभी-कभी सरकार भी मौका देती है। उदाहरण के लिए पिछली बार इंगलैंड की महारानी भारत पधारीं थीं। उनका हमने स्वागत किया जो कि हमको करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि वे जयपुर के महाराज के यहां जा कर ठहरीं और इस कारण गांवों में चुनाव के अवसर पर इस बात का प्रचार किया गया कि महारानी जयपुर का राज राजा को वापस दे गयीं।

**श्री रघुनाथ सिंह** ( वाराणसी ) : मिसेज कनैडी भी जयपुर में ठहरी थीं।

**श्री पहाड़िया** : और यह प्रचार किया गया कि जब राज वापस दे दिया गया तो जागीरदारों को जागीरें भी वापस कर दी गयीं और जब ऐसा हुआ तो जो छोटे छोटे जमींदार थे उनको भी जमींदारी वापस मिल गयीं। जब ऐसा प्रचार हो तो कौन गांव वाला यह हिम्मत कर सकता है कि इन लोगों के विरोध में खड़ा हो और इनके विरुद्ध वोट दे। इसका नतीजा यह हुआ कि ये लोग हमारे लोगों पर फिर से हावी हो गए। आपने जागीरदारी प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया था लेकिन उन लोगों ने दूसरे जरिए से वही स्थिति प्राप्त कर ली। आप देखें कि अगर कोई सरपंच चुना जाता है तो उसके पास कितना अधिकार हो जाता है और अगर कोई पंचायत समिति का प्रधान चुन लिया जाता है तो उसके नीचे तो बी० डी० ओ० भी रहता है। उसका प्रभाव गांव वालों पर बहुत होता है। तो इन सब बातों पर गौर किया जाना चाहिये और पंचायत राज के अन्तर्गत जो कर लगाने की व्यवस्था है उसको नियमित किया जाना चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि कौनसा टैक्स पंचायत ने लगाया है और कौनसा कांग्रेस ने लगाया है। लोगों को यह बताया जाना चाहिये कि कांग्रेस गांव की पंचायतों में टैक्स नहीं लगाती। एक मानी में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ये कर लगाती है क्योंकि कांग्रेस का राज है लेकिन पंचायत का कर सरकार तो नहीं लगाती। कभी कभी पंचायतें उन विषयों में भी टैक्स लगा देती है जो उनके अपने अधिकार में नहीं हैं। इसलिए इस बात का प्रबन्ध होना चाहिये

[श्री पहाड़िया]

कि पंचायतें अपने विषयों से अतिरिक्त विषयों में कर ना लगा सकें । इस बात का एक क्लेरिफिकेशन है कि कौनसा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, कौनसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है और कौनसा पंचायतें लगा सकती हैं । लेकिन देखने में आता है कि पंचायतें उन चीजों पर भी टैक्स लगा देती हैं जो उनके सबजेक्ट नहीं हैं और जब ऐसा होता है तो गांव के वे पढ़े लिखे लोगो को भ्रम हो जाता है और वह समझते हैं कि दिल्ली की सरकार ये कर लगा रही है । तो इस बात की सफाई होनी चाहिये और राज्य सरकारों को चाहिये कि पंचायतों के एक लिस्ट में जिसमें बताया गया हो कि पंचायतें कौनसे टैक्स लगा सकती हैं । जो उचित टैक्स हैं उनसे अधिक टैक्स पंचायतें न लगा सकें क्यों कि जनता उनको सहन नहीं कर सकती । अक्सर देखने में आता है कि पंचायत ऐसे टैक्स लगा देती है जिनको जनता सहन नहीं कर सकती ।

इसके साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । आपने अपने सामज वाद को लाने के नारे को पूरा करने के लिये गांवों में जो खेती की जमीन है उसकी एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी है कि इससे अधिक जमीन कोई किसान नहीं रख सकता । इस कारण गांवों में यह प्रचार चल रहा है कि यह कांग्रेस सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों और राजे महाराजों की आमदनी पर और उनकी जायदाद पर कोई सीमा नहीं लगाती पर खेती की जमीन पर सीमा लगाती है । शहरों में लोगों के पास लाखों रुपयों की जायदादें हैं उनकी सरकार ने कोई सीमा निश्चित नहीं की है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर संभव हो तो जिस तरह आपने गांवों में जमीन की सीमा निर्धारित की है इसी प्रकार शहरों की जायदाद की और शहर के लोगों की आमदनी की भी कोई सीमा निर्धारित करें । एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है उनकी जमीन पर आप सीमा लगाते हैं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक अमदनी है उस पर आप कोई सीमा नहीं लगाते ।

आप कहते हैं कि अगर हम आमदनी पर सीमा लगाएंगे तो लोगों का इनीशिएटिव खत्म हो जाएगा और देश की तरक्की रुक जाएगी । यह बात ठीक है । इसलिए यद्यपि मैं आमदनी की सीमा निश्चित करने के पक्ष में हूं लेकिन ऐसा करने से आप कहते हैं कि देश की उन्नति में बाधा पड़ती है इसलिए इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता । अभी कुछ समय आप चाहे इस पर सीमा न लगाए लेकिन जो बड़ी बड़ी जायदादें हैं उनकी सीमा आपको लगानी चाहिये । लोगों की आमदनी निश्चित करने पर तो मैं इसलिए जोर नहीं देना चाहता कि उस आमदनी से लोग, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ही सही, नए नए काम खोलते हैं जिससे लोगों को काम मिलता है । लेकिन जो बड़ी बड़ी जायदादें हैं उनकी तो सीमा होनी चाहिये । यह ठीक है कि आपने जायदादों पर कर लगाए हैं लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास अपार जायदादें हैं जिनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है । मेरा निवेदन है कि इस अचल सम्पत्ति पर आप और अधिक कर बढ़ाएं । मैं चल सम्पत्ति पर अधिक नियंत्रण लगाने पर जोर इसलिए नहीं देता कि उसे उपयोग करने से लोगों को काम मिलता है लेकिन अचल सम्पत्ति पर तो आपको ज्यादा से ज्यादा कर लगाने चाहिए । मैं तो कहूंगा कि अगर आप इसको एक्वायर कर सकें तो एक्वायर कर लें लेकिन अगर संविधान इसके मार्ग में बाधक होता हो तो आप कोई

ऐसी व्यवस्था करें कि इन जायदादों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए तकि इनका सही उपयोग हो सके। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो हमारे देश के सभी लोग ग़रीब हैं। जिसको पूछिए, वह अपने कारोबार से संतुष्ट नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा आई० सी० एस० आफिसर हो। रोज़गार करने वाला व्यापरी या उद्योगपति हो, कारखाने वाला हो या छोटे से छोटा नौकरी करने वाला हो, किसान हो या मजदूर हो, कोई भी संतुष्ट नहीं है और सब कहते हैं कि हम को अपना काम पसन्द नहीं है। लेकिन इस से काम नहीं चलने वाला है। हर एक को कोई न कोई काम तो करना ही पड़ेगा। जिसको अपना काम पसन्द नहीं है, वह उसको छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि जिन छोटे छोटे लोगों की कम आमदनी है, विशेष तौर पर जो सरकारी क्षेत्र में नौकर हैं, उन की आमदनी बढ़ाई जाये, जिसका अर्थ यह है कि उन की तन्ख्वाह बढ़ाई जायें। लेकिन उनको अधिक तन्ख्वाहें देने के लिये टैक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। यह ठीक है, लकिन दुनिया में जब अक्ल और श्रम की दौड़ लगती है और श्रमिक यह देखता है कि शहरों में एयर-कन्डीशन्ड मकानों में बैठ कर कुछ लोग दो चार घंटे फाइलों और कागजों का काम करते हैं और दो तीन हजार रुपया पाते हैं, जब कि गांवों में – और बड़े बड़े शहरों में भी –किसान और मजदूर सारा दिन, आठ, दस, बारह घंटे काम करते हैं, लेकिन इस के बावजूद उन को वह नहीं मिलता है, जो कि उनको मिलना चाहिये, तो वह थक कर बैठ जाता है और उस के मन में ईर्ष्या और स्पर्द्धा पैदा होती है कि मैं भी अपनी तरक्की की बात क्यों न सोचूं ।

इन परिस्थितियों में इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि उन लोगों के लिए मकानों, स्वास्थ्य-सेवाओं और शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध की जायें, ताकि उन को कुछ राहत मिल सके और उन का खर्च कुछ कम हो सके। जहां तक उन की आमदनी तन्ख्वाह को बढ़ाने का प्रश्न है, मंत्री महोदय खुद उसका कोई तरीका सोचें। अगर ऐसा किया जायेगा, तो वे लोग देश में हो रहे तरक्की के कामों में ज्यादा लगन और उत्साह के साथ काम करेंगे ।

हाल ही में सदन के सामने दो तीन विधेयक रखे गये, जिन में राज्यों में सैंट्रल टैक्सिज़ के वितरण की व्यवस्था की गयी है। मैं राजस्थान से आता हूं। फिनांस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस को काफी लाभ पहुंचा है और उस को मिलने वाला भाग लगभग दुगना हो गया है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जिन को मिलने वाले भाग में बहुत कमी होगई है। उदाहरण के लिए आप काश्मीर को लीजिए। वहां पर बहुत से विकास कार्य पड़े हुए हैं और उस राज्य का विकास करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन फिनांस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस का भाग कम हो गया है। अगर उस को मिलने वाली धन-राशि को बढ़ाया जाये, तो अच्छा होगा ।

फिनांस कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस आमदनी को बांटते समय इस बात का ध्यान रखा है कि किसी राज्य की आबादी कितनी है। मैं समझता हूं कि केवल आबादी को दृष्टि में रखने से काम नहीं चलेगा। कुछ इलाके ऐसे हैं– जैसे राजस्थान है– जहां की आबादी थोड़ी है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। बड़े एरिया– क्षेत्र के लिये ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। दिल्ली जैसी छोटी जगह में लगभग पांच पच्चीस लाख लोग रहते हैं, लेकिन राजस्थान में इतनी आबादी उस के एक चौथाई भाग में बसती है। वहां की स्थिति यह है कि गांव गांव के लिये कुंआ चाहिये। अगर यहां

[ श्री पहाड़िया ]

पर एक हैंड-पम्प लगा दिया जाये, तो हजारों आदमियों को उस से लाभ पहुंच सकता है, लेकिन अगर राजस्थान के किसी गांव में एक कुंआ बना दिया जाये, तो ज्यादा से ज्यादा दस, पच्चीस, पचास घरों को उस से फायदा पहुंचेगा। इस लिये ऐसे क्षेत्र के लिए ज्यादा धन चाहिये ।

इस लिए केवल आबादी और पिछड़ेपन के साथ ही साथ एरिया और विस्तार का भी ध्यान रखना चाहिये। तभी ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो सकता है, अन्यथा कुछ क्षेत्र कभी आगे नहीं बढ़ पायेंगे। जहां तक पिछड़ेपन का संबंध है उस का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है, इस लिए कि उस का एरिया, विस्तार इतना बढ़ा है कि अन्दाज लगाना मुश्किल हो जाता है।

हिन्दुस्तान में दो तीन तरह के लोग रहते हैं, जिन की चर्चा होती है। कुछ पैसे वाले हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं। लेकिन गरीब लोगों में भी एक तबका ऐसा है, जो कि अति गरीब है और जिसको वीकर सैक्शन आफ दी सोसायटी कहा जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि हरिजन ही वीकर सैक्शन आफ दि सोसायटी हैं। मैं अछूतों को ही अति गरीब नहीं मानता हूं। हरिजन तो निश्चिय रूप से गरीब हैं ही। उन की आमदनी का कोई जरिया नहीं है और उन को अब तक समान अवसर नहीं मिला है, लेकिन उन के अलावा और भी लोग ऐसे हैं, जिन की आमदनी का कोई जरिया नहीं है और जो वास्तविक अर्थों में वीकर सैक्शन्ज आफ दि सोसायटी हैं। सरकार ने उन को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्था तो की है, लेकिन उस का लाभ उन को नहीं मिल रहा है। शिक्षा की सुविधाओं और स्वास्थ्य-सेवाओं का लाभ गांवों के उन लोगों को नहीं पहुंच रहा है, जिन के पास पहुंचना चाहिये।

जैसा कि मैं ने कहा है, गरीबों में भी कुछ अति गरीब हैं, जो यह नहीं जानते कि देश में क्या हो रहा है। उन लोगों के लिए सरकार को खास इंतजाम करना चाहिये। जिस तरह हमने हरिजनों को संरक्षण दिया हुआ है, उसी तरह राज्य सरकार को और उनके जरिये कर्मचारियों को यह निर्देश देना चाहिये कि जो लोग वास्तव में गरीब हैं, जिनकी सरकार तक, या दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं है, उनको हमारी योजनाओं का विशेष लाभ मिलना चाहिये। इस समय स्थिति यह है कि हम लोगों में जो ज्यादा पैसे वाले ज्यादा आमदनी वाले हैं, वे लाभ उठा लेते हैं और वीकर सैक्शन्ज आफ दि सोसायटी वंचित रह जाते हैं और इस लिए इस बारे में बार-बार जो आलोचना होती है, वह एक मायने में सही मालूम होती है।

इस के अतिरिक्त योजनायें बनाते वक्त पिछड़े वर्गों का ध्यान रखा जाना चाहिये। मैं ने अभी राजस्थान की मिसाल दी है। जैसलमेर में तेल निकलने की चर्चा है, लेकिन आज तक उसमें प्रगति नहीं हो रही है। राजस्थान में तेल निकालने की व्यवस्था करने के साथ साथ कई कारखाने और दूसरे उद्योग भी पनप सकते हैं। चाहे बिजली का सवाल हो, तेल का सवाल हो या आने-जाने की सुविधायें प्रदान करने का सवाल हो, हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए इलाकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। वे इलाके ऐसे हैं जहां विकास का कोई काम नहीं हुआ है। अगर उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है और सरकार आबादी और पिछड़ेपन के दे आधारों को ले कर चलती रहती है, तो वे इलाके दस पन्द्रह साल तक लाभ नहीं उठा सकेंगे।

मैं पुनः माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुल्क में इस तरह की व्यवस्था कायम की है, जिस से

देश समाजवाद की तरफ जा रहा है और गरीबी मिटती जा रही है। जो सवाल मैं ने यहां पर रखे हैं, अगर उनकी तरफ भी ध्यान दिया जायेगा, तो देश में समाजवाद लाने में अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी।

**श्री रघुनाथ सिंह** : सभापति महोदय, इस बजट के सम्बन्ध में मैं काश्मीर के सम्बन्ध में एक दो शब्द कहना चाहता हूं, इस लिये कि काश्मीर हमारे देश का एक ऐसा सूबा है, जहां कम से कम चार देशों की सीमायें आ कर मिलती हैं। काश्मीर का दुर्भाग्य रहा है कि उस पर मुगल, पठान, सिख और डोगरा लोगों का शासन रहा है। वहां के लोगों को कभी भी स्वयं विकास करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ है। चार सौ वर्षों से काश्मीर पर दूसरों की सत्ता रही है। १९४८ में पहला मौका आया कि काश्मीर वालों को खुद अपना विकास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

जब हम काश्मीर के विषय में सोचते हैं, तो केवल काश्मीर उपत्यका, अर्थात् काश्मीर वैली, ही नहीं, बल्कि काश्मीर के दूसरे हिस्सों, जम्मू और लद्दाख, का भी खयाल रखना चाहिये। अगर आकुपाइड काश्मीर को छोड़ दें, तो इस वक्त काश्मीर की पापुलेशन करीब पैंतीस लाख है। दस लाख ऐसी है, जो कंडी एरिया अर्थात्, काश्मीर के बाहर पहाड़ और मैदान के बीच रहती है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाये, तो वह देखेगा कि कंडी एरिया के लोगों को पीने के लिये जल भी नहीं उपलब्ध है।

**Shri D. C. Sharma:** Had you been there?

**Shri Raghunath Singh:** Yes; twice, thrice.

पहाड़ में कूंए नहीं होते हैं। इस लिये बरसाती पानी छोटे छोटे तालाबों में इकट्ठा होता है। उसी पानी को जानवर भी पीता है आदमी भी पीता हैं। लेकिन जब से हमारे देश को आजादी मिली है, बख्शी साहब की सरकार ने दो तीन कुएं उस एरिया में लगवा दिये हैं जिससे कि कुछ लोगों को जल प्राप्त हो रहा है।

इस एरिया के आदमियों को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनके पैर टेढ़े हैं। बड़े खूबसूरत नौजवान हैं। वे, बड़े हट्टे कट्टे हैं। कमर से ऊपर का शरीर बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा तर आदमियों के पैर टेढ़े होते हैं। जानवर जिस तालाब से पानी पीता है अगर उसी तालाब से इंसान पानी पीने लग जाता है तो नहरुआ प्रकार की एक बीमारी पैर में होती है। पैर टेढ़ा हो जाता है। उदयपुर के एरिया में, मेवाड़ के एरिया में भी इसी प्रकार की बीमारी होती है। यही बीमारी कण्डी एरिया में होती है। यहां की दस लाख की आबादी के विषय में मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। उनके लिये जल का कोई सन्तोषजनक इंतिजाम कम से कम कर दें। यह बहुत ही पुण्य का काम होगा।

हमारे वेदों में भी काश्मीर शब्द का जिक्र आया है। "क" का अर्थ है "जल" और "समीर" का अर्थ होता है वायु, यानी इसका अर्थ हुआ "जलवायु" अर्थात अच्छा जल और अच्छी हवा। इसका अर्थ हुआ सुन्दर जलवायु। अतएव मैं कहना चाहता हूं कि इन दस लाख लोगों के लिये अगर केवल पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया जाये तो वित्त मंत्री महोदय एक बहुत बड़ा काम कर देंगे। इससे बढ़ कर पुण्य का और कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता।

पुराण में एक गाथा आती है। काश्मीर के एक दो नाम दिये गये हैं। एक नाम तो सतीदेश आता है। वूलर लेक का नाम सतीसर है। इस सतीदेश और इस देश की स्मृति में अगर गवर्नमेंट कम से कम जल का प्रबन्ध कर दे तो यह एक बहुत ही अच्छा कार्य समझा

[श्री रघुनाथ सिंह]

जायेगा । डोगरे युद्ध काल में बहुत बहादुरी से काम करते हैं । भूतकाल में किया है, उनका ध्यान रखते हुए भी आपको यह उपकार उन पर करना ही चाहिये ।

मैं काश्मीर में जाने का जो मार्ग है, उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं । सड़क द्वारा बनिहाल पास से हो कर पहुंचा जाता है । यदि इस मार्ग को किसी कारणवश रोक दिया जाये, बन्द कर दिया जाये तो मैं पूछना चाहता हूं कि काश्मीर की रक्षा किस प्रकार से कर सकेंगे । पुराणों में एक विवरण आता है । प्राचीनकाल में कांगड़ा देश से जिसको त्रिगत कहते हैं, उस त्रिगत देश से भद्रवा और किस्तवार तक जो काश्मीर के जिले हैं, उन तक एक मार्ग था । उस से लोग आया जाया करते थे । इसी मार्ग इसी मार्ग से तिब्बत को भी लोग जाते थे । मुगल रूट की भी बहुत सी बातें सुनने में आती हैं । मुगल रूट पीरपंजाल द्वारा जाता था । पीरपंजाल १२,००० फुट ऊंचा दर्रा है । वहां पर बर्फ पड़ेगी तो सम्भव है रास्ता साल में तीन चार महीने के लिये बन्द हो जाये । जबकि दूसरे हाइबे के बारे में लोग सोच रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे हाइबे के बजाये आप कांगड़ा से भद्रवा और किस्तवार को मिला दें तो जो रूट बनेगा इस रूट से आप जो भी सामग्री भेजना चाहें भेज सकेंगे । सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सामग्री भेजने की आवश्यकता महसूस हो तो वह इस रास्ते से आसानी से भेजी जा सकेगी । इस में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी पेश नहीं आयेगी । प्राचीनकाल में जब लोग काश्मीर जाया करते थे तो वे इसी रास्ते से जाया करते थे । मैं कहना चाहता हूं कि इस रास्ते का भी अन्वेषण करवाना चाहिये । सम्भव हो तो इस मार्ग को खुलवाना चाहिये ।

फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट में काश्मीर के साथ बे-इंसाफी हुई है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसको देखने से पता चलता है कि अगले पांच बरसों में काश्मीर को ७४ लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से कम मिलेगा । पांच वर्षों में कुल राशि ३ करोड़ ७० लाख के करीब हो जाती है । मेरे भाई पहाड़िया जी ने कहा है कि आर्थिक विकास करते समय केवल यही नहीं देखना चाहिये कि वहां की आबादी क्या है, जनसंख्या क्या है, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिये कि जो सहायता दी जा रही है, उस सहायता का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है । सुरक्षा दृष्टि से अगर आप देखें तो भी काश्मीर की सहायता आपको करनी चाहिये और अधिक से अधिक करनी चाहिये । अगर वहां पर कम्युनिकेशन और ट्रांस्पोर्ट का विस्तार किया गया तो इससे हिन्दुस्तान की रक्षा होगी । अतएव यह केवल आबादी का सवाल ही नहीं है । बल्कि सारे हिन्दुस्तान की रक्षा का सवाल है । चालीस करोड़ आदमियों का इससे गहरा सम्बन्ध है । आबादी को ही देख कर काश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार करें और जो रुपया उसकी ग्रांट से कम कर दिया गया है, ७४ लाख रुपया प्रतिवर्ष कम कर दिया गया है, उसे उसको दें । मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर यह कहना चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा रुपया आप काश्मीर को दें । काश्मीर का आज हम देखते हैं १७–१८ करोड़ का बजट है । वह एक सीमावर्ती प्रदेश है । यह जो सीमावर्ती सूबा है उस में १७–१८ करोड़ रुपये से क्या हो सकता है । डोगरा काल में काश्मीर का कुल चार करोड़ रुपये के करीब का बजट होता था जो आज बढ़ कर १७–१८ करोड़ का हो गया है । लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने की बात है कि मूल्यों में भी उसी हिसाब से वृद्धि हो गई है । आंध्र को आपने चार करोड़ के स्थान पर नौ करोड़ दिया है, मैसूर को ६ करोड़ के स्थान पर ६ करोड़ २५ लाख दिया है,

उड़ीसा को ३ करोड़ के स्थान पर ११ करोड़ दिया गया है, लेकिन काश्मीर के बारे में ७४ लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से ग्राट को कम कर दिया गया है । इस सिफारिश को हर्गिज भी न माना जाये बल्कि उसको तीन चार करोड़ रुपये की और भी मदद दी जाये । मैं ने आपसे निवेदन कर दिया है दस लाख आदमियों को पीने तक का पानी नहीं मिलता है और जो उसी तालाब से पानी पीते हैं जिससे जानवर पीते हैं, उस एरिया में अगर आप ट्यूबवैल लगा दें तो यह सब से बड़ा उपकार आप उन पर करेंगे ।

अब मैं लैह के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । एक समय था जब वह सूखा एरिया था । वहां पर अब दो तीन कुएं बन कर तैयार हो गये हैं । अगर कोई वहां बीस बरस पहले गया हो, वह अगर आज वहां जा कर देखे तो उसको जमीन आसमान का अन्तर मालूम पड़ेगा । जहां एक पत्ती तक नहीं उगती थी वहां आज हर हरे बाग हो गये हैं, खेती हो रही है और लोगों को पीने का पानी प्राप्त हो गया है । अगर आप काश्मीर को रुपया नहीं देंगे, उसका रुपया काट लेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि जो तरक्की वहां हो रही है, लेह में जो तरक्की हो रही है, वह सब रुक जायेगी और उसका विकास असम्भव हो जायेगा । चीन की सीमा उसके साथ लगती है, पाकिस्तान की सीमा उसके साथ लगती है और चीन की फौजें उसकी सीमा के साथ साथ खड़ी हैं, इस वास्ते लेह का विकास होना बहुत जरूरी है । आपको चाहिये कि आप उसकी शक्ति को बढ़ायें, उसको ताकतवर बनायें । लेकिन आपने तो उसकी ग्रांट की राशि ही ७४ लाख रुपया कम कर दी है । इसको न काट करके मैं तो यह कहूंगा कि उसको पांच छः करोड़ रुपया आप प्रतिवर्ष दें ताकि उसका और लेह का विकास हो सके ।

अब मैं कम्यूनिकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वहां कम्यूनिकेशन का मामला बहुत डिफिकल्ट हो गया है । तार की लाइन हमारे यहां से वहां नहीं है । जो काम अब हो रहा है वह रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा हो रहा है । कम्युनिकेशन के मामले में वहां बड़ी अव्यवस्था है । वहां टेलीफोन बहुत कम हैं । हिन्दुस्तान के जितने भी सूबे हैं, उन में से अगर सब से कम कहीं पर टेलीफोन हैं, सब से कम अगर कहीं पर तार घर हैं, सब से कम अगर कहीं पर पोस्ट आफिसिज़ हैं, तो वे जम्मू और काश्मीर में हैं । मैं तो कहूंगा कि एक तरह से बिल्कुल ही नहीं हैं । कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की वहां बड़ी भारी आवश्यकता है । इन की आजकल तो और भी अधिक आवश्यकता हो गई है क्योंकि वह हमारा सीमावर्ती इलाका है और एक तरफ उसके पाकिस्तान की फौजें खड़ी हैं और दूसरी तरफ चीन की खड़ी हैं । ऐसे समय में जितना अच्छा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का प्रबन्ध वहां होगा, उतनी ही शक्ति के साथ हम दूसरों का सामना कर सकेंगे । इस वास्ते इधर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

अब मैं पावर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । जब डोगरा रूल काश्मीर में था तो वहां सिर्फ एक पावर हाउस था और वह श्रीनगर में था और वहां पर बहुत थोड़ी शक्ति उत्पन्न होती थी । अब वहां पर दो तीन स्टेशन हैं और उन से शक्ति उत्पन्न हो रही है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर चनाब नदी जिस को हमारे प्राचीन शास्त्रों में चन्द्रभागा कहा गया है, और जिस में बहुत ज्यादा जल है, उसके उपयोग की कोई योजना बना लें तो सारे काश्मीर को हम एक ही स्थान से बिजली दे सकते हैं ।

काश्मीर में जो लोग गये हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां देवदार और चीड़ के बहुत

[श्री रघुनाथ सिंह]

बड़े बड़े जंगल हैं। जो रेयोन आज हम इस्तेमाल करते हैं, वह विदेशों से इम्पोर्ट होता है। जो रेयोन बनता है वह चीड़ और देवदार से बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चीड़ और देवदार के बड़े बड़े दरख्त हैं, जिन के जंगल के जंगल वहां पर हैं, उन का रेलवे के स्लीपर में उपयोग न कर के और कामों में इस्तेमाल किया जाये। उन से सुन्दर कागज बन सकता है, बैंक पेपर बन सकता है, साथ ही साथ रेयोन सिल्क अच्छा बन सकता है। उस की फैक्ट्रीज चाहे जम्मू में, चाहे भद्रवा में चाहे किस्तवार या काश्मीर वैली में आप खोलें तो देश की बड़ी भारी कमी दूर हो सकती है।

**14 hrs.**

आखिर में मैं कुछ इरिगेशन के सिलसिले में भी कहना चाहता हूं। काश्मीर की इरिगेशन की समस्या एक विचित्र समस्या है और उस के वास्ते अगर थोड़ा सा उपाय किया जाये तो बड़ा अच्छा हो। जैसा कि हमारे वायु पुराण में दिया हुआ है, पहले चार स्थानों में केसर की खेती अच्छी होती थी। एक किस्तवार में, दूसरे बलख में जिस को पहले वाहलीक कहा जाता था, तीसरे स्वात वैली में जिस को काफिरस्तान कहा जाता था। और चौथे काश्मीर वैली में। केसर की खेती काश्मीर में बहुत कम हो गई है। स्पेनिश केसर के सामने हमारे देश का केसर थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास का हो गया है। हमारा जो केसर है वह अच्छा नहीं होता। स्पेन का केसर सारी दुनिया में अच्छा होने लगा है। अगर किस्तवार में, जहां कि अच्छा केसर पैदा हो सकता है, अगर थोड़ा सा सिंचाई का प्रबन्ध हो सके तो काश्मीर का केसर हिन्दुस्तान के वास्ते ही नहीं काफी होगा बल्कि हम उस का एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान का केसर प्राचीन काल में सब से अच्छा माना जाता था। आज जो स्पेनिश केसर सब से अच्छा समझा जाता है उस का कारण यह है कि ४०० सालों तक काश्मीर में फारेन रूल होने के कारण वहां पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं था। खेती की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया इस लिये जो पुराने पौधे थे, पुराने खेत थे सब एक प्रकार से नष्ट हो गये। इस वास्ते मैं कहना चाहूंगा कि इरिगेशन का थोड़ा सा और प्रबन्ध काश्मीर में हो सके तो केसर की खेती वहां बहुत अच्छी हो सकती है। अब जो केसर होता है वह बहुत थोड़े एरिया में रह गया है और जहां पर और हो सकता है वहां पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इरिगेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाये। लेकिन यह सब होगा कैसे ? जब श्री देसाई की महान् कृपा होगी, दया होगी तभी ऐसा हो सकता है। जो ७४ लाख रु० वे काट रहे हैं वह तो दे ही दिया जाये, ४ या ५ लाख रु० ऊपर से दे दें तो आप की बड़ी कृपा होगी। कम से कम सती के देश में सती के पुत्रों को आप जलदान अवश्य करें।

**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : अब कितना केसर वहां पैदा हो रहा है ?

**श्री रघुनाथ सिंह** : बहुत कम। अब तो हिन्दुस्तान में स्पेन से केसर आता है।

**श्री राघेलाल व्यास** (उज्जैन) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उस का समर्थन करता हूं। यह सही है कि जब से हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ, तब से हमारा देश तरक्की के मार्ग पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब को इस बात का गर्व है कि जहां छोटी चीज, खास तौर से सीने की सुई और पेंसिलें हमारे देश में नहीं बनती थी, वहां अब बहुत कुछ उत्पादन इन वस्तुओं का हमारे देश में हो रहा है। लोगों की आय भी बहुत कुछ बढ़ी है और लोगों की हालत ज्यादा अच्छी हुई है।

लेकिन इस के साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि लोगों में एक यह भावना भी फैलती जा रही है कि जो शासन की मैशीनरी है, जो शासन की व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। लोगों में उस के प्रति कुछ नापसन्दगी है। जैसे कि आप टैक्स के मामले को ही लीजिये। आम तौर पर चर्चा होती है कि लोग टैक्स देने के खिलाफ नहीं हैं और न उन को ऐतराज है। वे कहते हैं कि टैक्स सरकार ले सकती है, लेकिन जो आपत्ति है वह यह है कि टैक्स की वसूली का जो तरीका है और टैक्स वसूल करने वाली जो मैशीनरी है सरकारी कर्मचारियों की, उस की वजह से लोग बड़े दुखी हैं। जो अनपढ़ लोग हैं उन को तो उस से बड़ी ही परेशानी है। किसी किसी जगह तो देखा गया है कि ३०, ३० और ३५, ३५ रुपये की वसूली में लोगों को काफी परेशानी होती है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब इस मसले पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

मैं नहीं कहता कि टैक्स कम किया जाये। अगर उस के बढ़ाने की भी जरूरत हो तो आप उसे बढ़ायें, लेकिन साथ ही लोगों की परेशानी को देखना चाहिये, ऐसा रास्ता निकाला जाय कि लोगों की परेशानी दूर हो। लोग यह नहीं चाहते हैं कि जो टैक्स वे देते हैं उस के देने से उन को ज्यादा परेशानी हो। कई बातों में आप ने इस परेशानी को अनुभव भी किया है। आप ने एक्साइज ड्यूटी लगाई और सेल्स टैक्स को घटाया। उस से लोगों की परेशानी कुछ दूर हुई। आज फिर यह देखने की जरूरत है कि क्या कोई पदार्थ ऐसे हैं, वस्तुयें ऐसी हैं जिन पर सेल्स टैक्स के बजाये एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सके। क्या आप इस तरह से सेल्स टैक्स को खत्म नहीं कर सकते? यह मानना होगा कि हमारे देश में शिक्षा की कमी है और छोटे छोटे व्यापारी ऐसे हैं जो छोटे छोटे उद्योग धन्धों और व्यापार को चलाते हैं। उन के पास इतना धन नहीं है, इतने उन के पास साधन नहीं हैं कि वे पढ़े लिखे मुनीम रख सकें और उस के द्वारा ऐसा इन्तजाम कर सकें कि उन को ज्यादा मुनाफा हो। इस के लिये वे कुछ खर्च कर सकें यह सम्भव नहीं है।

बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे कि अनाज वगैरह भरने वाले बोरे हैं, हेसियन क्लाथ है, उस के ऊपर अगर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाये तो कोई अधिक हर्ज नहीं है क्योंकि वह कोई ग्रामोद्योग में पैदा नहीं होता। यह बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी मिलों में बनता है और जूट से ही बनता है। उस पर आप जितनी एक्साइज ड्यूटी चाहें लगा दें, लेकिन आप को लोगों की परेशानी को जरूर देखना चाहिये। जो छोटे छोटे व्यापारी कहलाते हैं और परेशानियां उठाते हैं उन के ऊपर आप को विचार करना चाहिये कि क्या एक्साइज ड्यूटी के जरिये रकम वसूल कर के आप उन को बचा नहीं सकते। इसी तरह से और भी वस्तुयें हो सकती हैं।

आप एक कमिशन बिठलाइये जो कि सब जगह जाये, वह लोगों की बातों को जा कर सुने कि क्या क्या दिक्कतें उन को होती हैं। और छान बीन करने के बाद वह फिर से यह तय करे कि कौन से टैक्स के बजाये कौन सा टैक्स लगाया जाये। देश में भिन्न भिन्न राज्यों में टैक्स लगाने की पद्धति अलग अलग है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स हैं। सेल्स टैक्स भी भिन्न भिन्न प्रकार से लगाया जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरी जांच पड़ताल कर के देश में समानता अथवा यूनिफार्मिटी लाई जाये जिस से कि व्यापार पर कोई उल्टा असर न पड़े। यह पता लगाया जाये कि कहां सेल्स टैक्स कम है और कहां ज्यादा है, किस राज्य से दूसरे राज्य में स्मगलिंग होती है। इसे रोकने का इलाज केवल एक ही हो सकता है कि सभी राज्यों के फाइनेन्स मिनिस्टर्स

[ श्री राघे लाल व्यास ]

की एक कान्फरेंस हो । मैं समझता हूं कि फाइनेन्स कमिशन ने भी यह सुझाव दिया है कि टैक्स के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये एक कमिशन बैठे । सब राज्यों में समान रूप से टैक्स लिया जाये और ठीक तरह से लिया जाया करे । टैक्सों के रेट में कमी की जाये, इस के लिये भी आप को विचार करने की जरूरत है ।

जो शासन की मशीनरी है उस के बारे में भी आम तौर पर लोगों में चर्चायें होती हैं । मैं ने देखा कि जहां भी मैं जाता हूं वहां रिश्वत की ही बात होती है या फिर लाल फीते शाही की बात होती है । यह सही है कि कांग्रेसी शासन ने काफी कायदे कानून में परिवर्तन किये और कुछ ऐसे कदम भी उठाये जिन से रिश्वत कम हो, लेकिन यह मानना होगा कि इस वक्त लोगों को शिकायतें हैं । कहीं कहीं तो लोग प्लैन बना कर व्यवस्थित ढंग से रिश्वतें लेते हैं । इस को रोकने की बड़ी जरूरत है । जनतन्त्र में जहां जनता का राज्य हो अगर लोगों को इस किस्म की शिकायत है तो उसे खत्म किया जाना चाहिये । यह भी सही है कि कहीं पर डिमाक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और कहीं हो रहा है और कोआपरेटिव्ज के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अपना कारोबार चलाना चाहते हैं और जनता तथा देश का काम करना चाहते हैं । यह भी सही है कि इधर लोगों को शिकायत का मौका कम मिला, लेकिन बावजूद इस के कि शिकायतें हैं लाल फीते शाही और रिश्वतखोरी की, इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है और ऐसे उपाय आप को निकालने चाहियें जिन से लोगों को ऐसा अनुभव हो कि यह जनता का राज्य है । जो हमारे सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं उन की मनोवृत्ति अभी नहीं तब्दील हुई है । यह जरूर है कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंट एरियाज मे जो अधिकारी हैं उन के पुराने व्यवहार में और तौर तरीकों में कुछ परिवर्तन हुआ है, वे लोगों से मिल कर चलने लगे हैं, लेकिन इस के बावजूद लोगों को शिकायतों का मौका मिलता है । इस लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । हमारी पहली पंचवर्षीय योजना ने, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने और तीसरी पंचवर्षीय योजना ने इस बात पर अधिक जोर दिया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में जितना काम होना चाहिये वह अभी नहीं हुआ है । इस पर इस पर गम्भीरता से विचार करने की और इस मे सुधार करने की जरूरत है ।

कुछ पिछड़े हुए प्रदेश हैं खास तौर से जहां जहां आने जाने के मार्ग वगैरह नहीं हैं और इसके बारे में मेरे पूर्व वक्ता कुछ मित्रों ने आपके सामने अपने विचार रखे हैं । मैं भी इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

फाइनेन्स कमीशन ने खास तौर से इस बात पर जोर दिया है कि जिन राज्यों मे आने जाने के साधन नहीं हैं या कम हैं उनको विशेष सहायता दी जाये । यह सही है कि जो मेम्बर सेक्रेटरी हैं उन्होंने इससे असहमति प्रकट की है, लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनीफैस्टो में इस बात का वचन दिया है और वायदा किया है कि हर गांव को एप्रोच रोड दी जायेगी । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश मे जो योजना है उसमें जो रुपया सड़कों के लिये आपने रखा है उससे आपका यह वायदा पूरा हो सकेगा । गांवों के लोगों की यह मांग है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना मे हर गांव को एप्रोच रोड दी जाये ।

**Shri Morarji Desai:** Is it the expectation of anybody that in the Third Plan every village will have a road? It is something of a wonderful expectation of anybody in the country.

**Shri Radhelal Vyas:** That is in the Congress Election Manifesto. You prepared it and placed it before the public. You kindly go through that.

**Shri Morarji Desai:** I have gone through it.

**Shri Radhelal Vyas:** I myself wondered whether it could be ever possible.

**Mr. Chairman:** No; only if it is more than 5 miles.

**Shri Radhelal Vyas:** That is in the Plan; and this is in the Election Manifesto.

**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : उस में बीस वर्ष की अवधि दी गयी है ।

**श्री राधे लाल व्यास** : जी नहीं आप पढ़िए ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने पढ़ा है और मैं फिर माननीय सदस्य से कहूंगी कि १९८१ तक यह योजना है कि हर गांव में विलेज रोड बना दी जाये जिसका सम्बन्ध उस पक्की सड़क से हो जो तीन से पांच मील की दूरी तक हो ।

**श्री राधे लाल व्यास** : मैं आपको बता दूंगा । इलेक्शन मैनीफैस्टो में यही है ।

मैं फिर कहूंगा कि फाइनेन्स कमीशन ने इस बात को अनुभव किया कि कई राज्यों में अभी आने जाने के साधन नहीं हैं । हम अपने गांवों को पिछले १४–१५ साल में आने जाने के साधन तक नहीं दे सके । अगर आप उनको अभी सड़कें नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन नदियों पर पुल तो बनवा दें जिनके कारण वे बरसात के मौसम में बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं । चार पांच महीने तक अनेक क्षेत्रों के लोग कहीं आ जा नहीं सकते । मेरे क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं । क्या उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये । अगर आप अभी सब गांवों को सड़कें नहीं दे सकते तो कम से कम तीसरी योजना में इतना तो कर दीजिये कि नदी के बहाव के कारण कोई बीमार अस्पताल तक जाने से तो वंचित न रहे । आज मेरे प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जो दो दो नदियों के बीच में पड़ते हैं । ये लोग बरसात में सब तरफ से घिर जाते हैं और कहीं आ जा नहीं सकते । अगर इन नदियों पर पुल बनाया जाये तो यहां के लोग दस पन्द्रह हजार तक रुपया चन्दा करके देने को तैयार हैं और मेहनत भी करने को तैयार हैं । पिछली पंचवर्षीय योजना में विलेज रोड्स के लिये कुछ रुपया रखा गया था और उसमें यह प्रावधान था कि ७५ पर सेंट सेंट्रल गवर्टमेंट देगी और २५ प्रतिशत पब्लिक या स्टेट गवर्नमेंट देगी । मुझे पता नहीं की तीसरी योजना में कोई ऐसा प्रावधान रखा गया है या नहीं । अगर नहीं रखा गया है तो कुछ रुपया जरूर तीसरी योजना में इस बात के लिये रखें कि जहां के लोग रुपया देने को और मेहनत करने को तैयार हों वहां उनको आने जाने का साधन निर्माण करने में सहायता दी जाये । ऐसा करने से वहां के लोगों की कठिनाई दूर हो सकेगी ।

फाइनेंस कमीशन ने मध्य प्रदेश के लिये सात करोड़ की सड़कों के लिये सिफारिश की है और उड़ीसा के लिये भी इसी तरह की सिफारिश की है क्योंकि इन प्रदेशों में सड़कें बहुत कम हैं । फाइनेन्स कमीशन ने कहा है कि टैक्सेशन का बटवारा आबादी के लिहाज से और जो रुपया वहां वसूल होता है उसके लिहाज से किया जाये लेकिन केवल यही लिहाज नहीं रखा जाना चाहिये । प्रदेश की स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । जो गांव दूर हैं या जो पास हैं उन सब में आने जाने की सुविधा देनी चाहिये ।

इसी तरह से पीने के पानी की सुविधा भी आम जनता को मिलनी चाहिये । इस

[श्री राघे लाल व्यास]

बारे में सभी राज्यों की स्थिति को देख कर हमको विचार करना चाहिये ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि फाइनेन्स कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिये और खास तौर से जिन राज्यों के लिये सड़कों के वास्ते जितने रुपये की सिफारिश की है उतना रुपया उनको मिलना चाहिये ।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमको समाजवादी समाज की रचना करनी है और एक समृद्ध देश बनाना है और एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित करनी है । लेकिन यह काम बड़ी बड़ी डिगरियां या डिपलोमा वाले लोग पैदा करने से या ऐसे लोग पैदा करने से जिनके पास फर्स्ट क्लास या सैकिंग क्लास के सरटिफिकेट हों पूरा नहीं हो सकेगा । इनसे देश का काम नहीं चलेगा । आज आवश्यकता इस बात की है कि देश का मारल ऊंचा होना चाहिये । आज हर जगह, दफ्तरों में, स्कूलों में, कारखानों में, यह शिकायत सुनने में आती है हमारा मारल गिर रहा है । हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन पर दिन शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वह लोगों को बेईमान बनाती जा रही है । हम देखते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आज स्थिति यह है कि आज से २५ साल पहले जो मारल था उससे नीचे जा रहा है । मेरा विचार यह है कि जब तक हम स्कूलों में लड़कों को मारल की शिक्षा नहीं देंगे और विद्यार्थियों का बोर्डिंग हाउस में रखने का प्रबन्ध नहीं करेंगे जहां उन पर अच्छी निगरानी रह सके, तब तक इस दिशा में उन्नति नहीं हो सकती । आज हम देखते हैं कि स्कूलों में दो दो और तीन तीन शिफ्ट चलते हैं । जो बच्चे सुबह से दोपहर तक स्कूल में रहते हैं वे बाद में दिन भर खेलते हैं और अपना समय नष्ट करते हैं और सिनेमा देखते हैं । तो जब तक विद्यार्थियों के लिये ज्यादा से ज्यादा बोर्डिंग हाउसेज का प्रबन्ध नहीं किया जाता जहां पर कि बोर्डिंग का सुपरिटेंडेंट उनकी ठीक से निगरानी कर और उसको नियंत्रण में रख सके, तब तक शिक्षा से जो लाभ हम चाहते हैं वह नहीं हो सकता । ऐसी व्यवस्था किये बिना हम जनता का पैसा खर्च करते चले जायें उससे लाभ नहीं हो सकता । इसके लिये उचित प्रोग्राम बनाना चाहिये । ऐसे कोर्स बनाने चाहिये कि पढ़ने वाले अपने मारल्स को ज्यादा महत्व दें और उनका ध्यान चरित्र निर्माण की ओर जाये । ऐसा होगा तभी हमारे विद्योर्थी अच्छे नागरिक बन सकेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमने जो भी काम उठाए हैं उनमें हमको पूरी सफलना मिलेगी ।

**डा० मा० श्री अणे** : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । क्या माननीय वक्ता का ऐसा अनुभव है कि जो विद्यार्थी होस्टल्स में रह कर पढ़ते हैं उनकी नीति मत्ता बाहर रह कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से ज्यादा अच्छी होती है ।

**श्री राघे लाल व्यास** : ऐसा तो मैं नहीं मानता कि केवल बोर्डिंग में रहने मात्र से सब कुछ हो जायेगा । लेकिन अगर विद्यार्थी बोर्डिंग में रहेंगे और उन पर बोर्डिंग का सुपरिटेंडेंट निगरानी रखेगा और उनको उचित गाइडेंस देता रहेगा तो उनको बहुत लाभ होगा । यह सुपरिटेंडेंट स्वयं चरित्रवान होना चाहिये तो वह उन को प्रभावित कर सकता है और उनके चिरत्र निर्माण में बहुत सहायक हो सकता है । मेरा विचार है कि यदि ऐसा प्रबन्ध किया जाये तो विद्यार्थियों में उच्च चरित्र का निर्माण होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है । हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये आज करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, बहुत से मैडिकल कालिज

भी खोले गये हैं, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ायी गयी है । और डाक्टर भी काफी तैयार हो रहे हैं । लेकिन आज हम देखते हैं कि फिर भी आम जनता को राहत नहीं मिल रही है । अस्पतालों में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है । उनमें एडमिशन पाने के लिये बड़े बड़े क्यू लगे रहते हैं । बीमारियां बढ़ती जा रही हैं । मेरा विचार है कि रोगों को रोकने पर जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है और उसी का यह परिणाम है । मैंने पहले भी इस सवाल को उठाया है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । मेरा विश्वास है कि बहुत सी बीमारियों के पैदा होने का कारण यह है कि हमारी नदियों में गन्दा पानी दिनों-दिनो अधिकाधिक मात्रा में जा रहा है । जैसे जैसे नए उद्योग बढ़े जाते हैं अधिकाधिक मात्रा में गन्दा पानी नदियों में जा रहा है । आप देखें कि दूसरे देशों ने इसको रोकने के क्या क्या प्रबन्ध किये हैं। हमको उन देशों के अनुभव से लाभ उठाकर अपने देश में इस गन्दगी को नदियों में जाने से रोकने का प्रबन्ध करना चाहिये । हमको शहरों में अंडर ग्राउंड सीवेज आदि की व्यवस्था करके इस गन्दगी को नदियों में जाने से रोकना चाहिये । क्या जब तमाम उद्योगों की स्थापना हो चुकेगी और लोगों का स्वास्थ्य, जो कि अभी भी अच्छा नहीं है, और भी खराब हो चुकेगा, तब इस चीज पर ध्यान दिया जायेगा कि नदियों में गन्दा पानी न मिलने पाये । जब तक हम इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तब तक स्वास्थ्य के लिये करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी जनता को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे । अगर गन्दे पानी को नदियों में जाने से रोका जायेगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शासन को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा । मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक क्यों नहीं गया । इस ओर ध्यान देने की बड़ी जरूरत है । बहुत सा ऐसा खर्चा है जो अनावश्यक है और उसमें इकोनोमी हो सकती है । आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम खर्च को घटायें और इकोनोमी करें । हमें बहुत ज्यादा रुपया चाहिये निर्माण कार्यों के लिये । हमें बाहर से रुपया सहायता के रूप में मिल रहा है, स्माल सेविंगज से भी हम रुपया एकत्र कर रहे हैं, कर्ज भी हम ले रहे हैं लेकिन फिर भी जैसे-जैसे हमारा प्लान आगे बढ़ता जायेगा हमारा खर्चा भी बढ़ता जायेगा । हमें चाहिये कि हम देखें कि क्या कोई बेजा खर्चा तो नहीं हो रहा है, ऐसा खर्चा तो नहीं हो रहा है जो नहीं किया जाना चाहिये । हमारे यहां नये-नये कारखानों की स्थापना की जा रही है । हैवी ईलैक्ट्रिकल्ज कारखाना हमारे यहां स्थापित हुआ है । हम लोग वहां गये थे । वहां पर उस वक्त काफी लोग नौकरी पर रख लिये गये थे हालांकि काम शुरू नहीं हुआ था और इतने आदमी रखने की कोई जरूरत नहीं थी । हमने देखा है कि जिन दफ्तरों में काम ज्यादा है और वहां आदमियों की जरूरत है वहां पर आदमी तो दिये नहीं जाते हैं लेकिन जहां आदमियों की जरूरत नहीं वहां पर दे दिये जाते हैं । एक तरफ कहा जाता है कि हमारे पास रुपये की कमी है, हमारे साधन अधिक नहीं हैं लेकिन दूसरी तरफ वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हो रहा है । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है और इस की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । एक तरफ इतना काम होता है कि आदमी मिलते नहीं हैं और दूसरी तरफ काम होता नहीं है और आदमी नियुक्त कर लिये जाते हैं । उनको पूरी तनख्वाह महीने-महीने की मिलती रहती है । कितनी ही मिसालें मैं आपको दे सकता हूं । मशीन टूल्ज फैक्ट्री बनी । शुरू शुरू में वहां बहुत रुपया वेस्ट किया गया सर्वे पर, बार-बार रिपोर्ट लेने पर । यह सब कुछ हो चुकने के बाद वहां पर ठीक ढंग से काम शुरू हुआ । दफ्तरों में भी हम देखते हैं कि डुप्लीकेशन कई जगहों पर होता है । जहां पर कम खर्च होना चाहिये वहां पर ज्यादा खर्च किया जाता है । मुझे याद है एक बार हमने एस्टीमेट्स कमेटी में एक सैक्रेट्री से पूछा तो

[ श्री राघेलाल व्यास ]

उन्होंने कहा कि अगर मेरे पर छोड़ दिया जाये तो मैं बहुत कुछ खर्चे को कम कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब रास्ते में आते हैं और कहते हैं कि अनएम्पलायमेंट हो जायेगा अगर रिट्रेंचमेंट की गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह आपके वक्त की बात नहीं हैं, छः सात साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि सम परसंज़ विल बी थ्रोन आउट आफ एम्पलायमेंट अगर रिट्रेंचमेंट किया गया। वह एक जिम्मेदार सैक्रेट्री थे। उन्होंने यह बात मीटिंग में नहीं अलहदा कही थी। मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम आपको बतलाऊं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वह एक जिम्मेदार अधिकारी थे और आगे भी उन्होंने तरक्की की और बड़े-बड़े पदों पर वह रहे। इस वास्ते आपका ध्यान इस तरह की बातों की ओर जाना चाहिये और आपको देखना चाहिये कहां पर खर्चे में कमी की जा सकती है।

हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। उनके दौरान में बहुत सी ऐसी बातें हमारे नोटिस में आई हैं जो गलत थीं। उनके दौरान में बहुत सा गलत प्रापेगंडा किया गया। इस तरह के गलत प्रापेगंडा को रोकने का कोई न कोई इंतिजाम आपकी तरफ से होना चाहिए। हमने प्रजातन्त्र के रास्ते पर चलने का फैसला किया है और पिछले कई सालों से इसी रास्ते पर चलते आ रहे हैं। हमने इन इलेक्शनों में देखा है कि कुछ लोगों ने और कुछ साम्प्रदायिक संस्थाओं आदि ने भोली भाली जनता को, सीधी सादी जनता को अलत सलत प्रापेगंडा करके बहकाने की कोशिश की है। इस तरह से प्रापेगंडा को रोका नहीं गया है। यह कहा जा सकता है कि अगर कोई गलत बात की गई है कोई कोरप्ट प्रैक्टिस की गई है तो उसको लेकर इलेक्शन पेटीशन दायर की जा सकती है और चुनाव रद्द करवाया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर एक ऑर्डिनरी आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी गलत बातें तभी रुक सकती हैं अगर इस तरह के अपराधों को कागनिजेबल आफेंस करार दे दिया जाए, ऐसा अपराध करार दे दिया जाए जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर सके। अगर ऐसा किया गया तब तो इस तरह की चीजें रुक सकती हैं अन्यथा नहीं। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। बैलट पेपर्ज़ पर इस बार क्रास लगाया जाता था बैलों पर या दूसरों पर। लोगों ने प्रचार किया कि बैलों पर क्रास लगाने का मतलब है बैलों को काटना और अगर शेर पर क्रास लगाया जाता है तो इसका मतलब होगा शेर को काटना। अब बताओ कि बैलों को कटवाना चाहते हो या शेरों को कटवाना चाहते हो। भोली भाली जनता को क्या मालूम, उसने कह दिया कि हम शेरों को कटवाना चाहते हैं न कि बैलों को और इसलिये जाकर के उसने शेरों पर क्रास लगा दिया। इस तरह की बहुत सी बातें हुई हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी है, इस तरह की मैं आपको और भी कई मिसालें दे सकता हूं लेकिन ऐसा करने के लिये मेरे पास समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये गम्भीर बातें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। हर एक पार्टी को और हर एक उम्मीदवार को यह अधिकार है कि वह अपने हक में प्रचार करे, अपने उसूल या पार्टी के उसूल लोगों के सामने रखे नीति रखे लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं हो सकता है कि वह लोगों को गुमराह करे या गलत बातें करे। अगर इस तरह की बातों की इजाजत दी जाती है तो ये देश के लिये घातक सिद्ध होगी। ऐसी बातों को रोकना, ऐसे प्रचार को रोकना सरकार का फर्ज है और हमें चाहिये कि हम इस बारे में कोई ठोस कदम उठायें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रजातन्त्र को बहुत भारी धक्का लगेगा।

अब मैं गोवध के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इसके बारे में भी काफी प्रचार होता है । इसको लेकर हमारी पार्लियामेंट में कई बार प्रश्न उठा है । अटार्नी जनरल भी यहां आए थे और उनकी राय थी कि यह कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती है, केवल राज्य सरकारें ही बना सकती हैं। यह सही है कि कई राज्य सरकारों ने गोवध निषेध कानून बना लिये हैं लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां गोवध होता है । मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें प्रजातन्त्र में प्रजा की भावनाओं का, प्रजा के मत का प्रजा के विश्वासों का आदर करना चाहिये । इसी बात को देख कर अकबर बादशाह ने गोवध निषेध किया था । अगर सरकार किसी बात को गलत भी समझती है तो जनमत को अनुकूल करके, लोक शिक्षण के द्वारा लोगों के दिलों को बदलना चाहिए, उनके मतों को, उनके विचारों को बदलना चाहिए । अगर कोई सामाजिक सुधार लाना हो या दूसरा सुधार लाना हो तो उनकी सलाह से, उनकी मर्जी से हम ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज देश में यह भावना है आम तौर से कि सभी लोगों में कि गोवध नहीं होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोवध बिल्कुल निषेध किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए अगर संविधान को भी बदलना पड़े और यह अधिकार पार्लियामेंट से लेना पड़े तो वह भी करना चाहिए । अगर अभी भी कुछ राज्यों में गोवध होता है तो केन्द्र को अपने प्रभाव को काम में ला कर, हमारे नेतागणों को अपने प्रभाव को काम में लाकर उन राज्यों से भी ऐसे ही कानून बनाने का आग्रह करना चाहिए जिससे गोवध निषेध हो ।

यह कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है क्रोम लेदर वगैरह और क्रोम लेदर मरे हुए जानवरों की चमड़ी से नहीं बनता है। जहां इतना साइंटिफिक डिवेलेपमेंट हो चुका है, इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है, वह क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता है कि मरे हुए ढोर की चमड़ी से क्रोम लेदर बन सके, अच्छा चमड़ा बन सके और क्या यह कोई असम्भव बात है ? मैं समझता हूं कि यह आसानी से हो सकता है। जानवर हमेशा के लिये अमर हो कर नहीं आया है, वह मरेगा ही और उसकी चमड़ी देश में ही रहने वाली है, वह गल नहीं जायेगी इस वास्ते वैज्ञानिक तरीके से उस चमड़ी को ठीक और अच्छा बनाने की कोई विधि निकाली जानी चाहिए और लोगों में आम तौर से जो यह भावना है कि गोवध बन्द होना चाहिए और जो उपयोगी पशु हैं उनका वध निषेध होना चाहिए और जिसको लेकर उनमें बहुत बड़ी नाराजगी है, उसका आपको आदर करना चाहिए और इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए ।

**Shri Warior** (Trichur): Sir, I shall make only brief comments on this Budget since it is an interim Budget. We hope that many of us will come again and have a full-dress debate. It is a deficit Budget this time also and so the apprehension is there. When the frogs croak, it means that rain is coming. So, when the Budget has a deficit, the taxes are coming. Last time we were told that the deficit was small and still new taxes came and the Finance Minister was pleased to reduce the aggregate taxes by a few crores. This time the deficit is much more—10 15 times more. The new taes are not known yet. Though the new taxes will be a small proportion of the whole Budget, what is outstanding in the mind of the people is the new taxes. Anyhow, new taxes are the only source by which this deficit could be balanced. Once taxes are imposed any Government and for that matter any Finance Minister will be very reluctant to reduce the taxes. No relief could be evpected from any Finance Minister once the taxes are imposed. Taxes go up; they never

[Shri Warior]

come down. That is our experience during the last fifteen years or at least during the last ten years of our plan period. The expenditure side is increasing and hence there is a popular apprehension that there will be new taxes and new burdens on the people. It is not that nobody is unwilling to pay to the Government exchequer for that is an absolute necessity as far the administration is concerned as also for capital investments and other development programmes. Nobody is unwilling to pay any taxes, however much the people should have their belts tightened. Yet, at the same time, as Shri N. R. Muniswamy very rightly said, even though we may try to make people understand that these are absolute necessities, because of so many other reports coming about, the people have a well-grounded apprehension that all is not well with the money they are giving to the Government as taxes.

In this respect, apart from the audit reports, I should like the Government, especially the Finance Ministry, to take more cognizance of the repeated criticisms in the reports of the Public Accounts Committee and also the Estimates Committee, that have been laid before the House from time to time. The reports of both the Public Accounts Committee and the Estimates Committee give ample scope for the people for having the impression that there is much to be done and improved in budgeting.

Apart from the usual cases of overlapping, there are so many items which are not properly estimated and which are not properly implemented also. So, not only in the figures but in actual, practical life, when we see these things going on in the country, one will find that not only do the people come across much wasteful expenditure but even expenditure which could not only be avoided but that in which the scheme is not even implemented. There are very essential schemes and projects which, if implemented, could benefit the people. But, without providing a machinery to implement them, the demands are placed and passed here. The appropriation is made and finally, We find that the amount could not be utilised. At the same time, the people's demand that they have a necessity for these plans and projects goes unfulfilled. So, without a proper machinery for implementing those schemes and projects, the Finance Ministry is coming here with the demands. The Finance Ministry alone is not the culprit in this respect. All the Ministries are, because they prepare the schemes without knowing fully well whether they can be implemented or not, and they give all the schemes to the Finance Ministry in the budget from. The budget is then presented here. We have no time to scrutinise it fully, because Parliament cannot afford to spend so much time on these things. We do not know whether these amounts will be actually spent or not. Many of these items are only known after four or five years; not even at the time of the budget or the revised budget or even when the actual accounts come, but only, later, when the audit reports are presented. Only then do we find that there are so many items.

It will be astounding to know that about Rs. 243 crores was the amount saved out of the budgetary allotment of a year. It is not a mean amount. Look at the deficit of Rs. 63 crores, and an annual saving of about Rs. 50 crores or Rs. 60 a year. Within five years, if you can save Rs. 240 crores, where is the deficit, and what is the necessity for new taxation? Hence, what I want to impress upon the Finance Minister is, if the Ministry had taken cognisance of these criticism and looked into the budgeting and made it a more proper and realistic budget, much of the burden could not have been imposed on the people.

I do not mince matters here. We know that tax must be paid and you

can impose heavy taxes also on the people, but then, you are not spending the money properly. At the same time, you are showing a deficit, and deficit is the only justification for new taxation! That is the first criticism that I have to make on the budget on the floor of this House.

When I make this criticism, I am not without any grounds. In the Audit Report for 1961, details of "entirly unnecessary supplementary grants and appropriations are given." In paragraph 3, at page 3 of the Central Government's appropriation accounts including proforma commercial accounts, for the year 1961, it is stated as follows:

> "The funds obtained by Supplementary Grants/Appropriations in a number of cases proved unnecessary or largely in excess of the requirements. These were obtained mostly in March, 1960 and resulted in large savings under the grants as a whole. In some cases, the savings were surrendered partly".

The statement is given at the end of the paragraph.

Then, under Savings in Grants and Appropriations, it is written as follows:

> "Savings aggregating to Rs. 260 crores occurred in 123 and 29 Grants and Appropriations out of 132 and 36 Grants and Appropriations respectiely."

The comparative position is also given as follows:

1957-58-Rs. 225 crores; 1958-59 Rs. 443 crores; 1959-60-Rs. 260 crores. So, where was the necessity for new taxation? Where was the necessity to find new money through new taxation? Where was the deficit? The deficit is simply the result of not scrutinising the estimates when the demands are made. If there had been scrutiny and proper checking up, these deficits would not have been there in the budget is faulty. That is the only conclusion we can arrive at.

I have thus far mentioned about the appropriations not used at all. There are partial appropriations also, partially utilised and partially saved. This is the way in which the budget is also made faulty.

Not only that. Another very interesting item has come to our knowledge. After these appropriations are made, where is the money kept? In para 15 of the Audit Report for 1956, in the Delhi accounts, there had been unauthorised opening of current accounts in a bank outside Government account, to which reference had been made. An officer opened in 1948 several current acounts with the Imperial (now State) Bank of India, outside the Government account without the sanction of the competent authority. The following irregularities were noticed in audit:

> "(i) to prevent lapse of budget grant sums aggregating about Rs. 1,50,000 were drawn from the Treasury for purchase of stores twoards the close of the financial year 1953-54 and deposited into current accounts, Most of the stores were actually purchased in the year 1954-55."

The grants were made in the previous year, but actually the appropriated amount is spent only in the following year. Then, where was the amount kept? Suppose the grant is not utilised, the appropriated amount is not utilised, naturally the regulation is that it must be refunded and surrendered. Instead of surrendering it, this gentleman thought that after surrendering, it is very difficult to come to Parliament again and ask for the grant of the demand. So, he kept it in an account which was not the Government account. The account was a private one, something in which the could freely operate without the knowledge of this superior authorities. Further, it was not a paltry amount.

[Shri Warior]

The next sub-paragraph says as follows:

"(ii) The departmental revenue recipts, Central Grants for disbursement of loans and sums received in repayment of loans, were not credited into the Treasury as required under the rules but were deposited into the current accounts."

Further, it is said as follows:

(iii) The balances in the current accounts at the close of the financial year were carried forward to the following year and not credited to Government as required by the rules."

These are some of the things found in the audit reports. If the audit reports are well scrutinised, invariably there is ground for these objections raised by the audit department.

Then, there are many projects. I will give an instance from the public Accounts Comittee's report to show how crores of rupees are wasted. I am referring to the 39th Report on D. V. C. for the year 1959-60 by the Public Accounts Committee. It is contained in page 7 of the PAC Report, 1961-62, where a very illustrative description is given about how amounts are spent. The pertinent point is about an irrigation *cum* navigation canal. The canal has not got enough water even for irrigation, but the authorities wanted to have it both irrigational and navigational. In the meantime, some incident happened there, which caused a loss of a few lakhs of rupees. After that, both irrigation and navigation are stopped Now, only if another dam is constructed, we will know whether this canal can be used or not.

You will be amazed to find from para 21 page 7 that:

"The comittee were informed in evidence that the original traffic estimates were drawn up by a Committee consisting of the representatives of the Corporation, the Ministry of Railways. Calcutta Port Trust and collieries. On the basis of the then available data regarding goods traffic between Calcutta and Durgapur and the over-stretched capacity of the Railways, the Committee made a rough estimate of the volume of traffic that the canal would attract. The estimates took into account the freight rates proposed to be charged by the Corporation which were lower than the existing charges for traffic by road and rail. The estimates had since been revised and according to the present indications, even an annual traffic of 7 lakh tons for the first few years, as estimated by the D.V.C. advisory Committee in June, 1958, appear to be an over-estimate. From the extent of revision, it is obvious that the original estimates regarding canal traffic were conjectural. As the canal has hardly been used for navigational purposes so far, the revision in the estimates of traffic is of no practical significance."

What was the amount spent? About Rs. 4 crores or Rs. 5 crores, which proved to be an infructuous expenditure. We do not know whether that canal can be used, even if another dam is constructed, because it is all when this canal goes down, they say, it can be converted into an irrigational and navigational canal, when there is not even drinking water in that canal. And, for this the people must pay!

I call particular attention to these things with no other intention or motive; let me be frank with the Finance Minister in that respect. Because of our experience in these matters, we find that there is nothing to be wondered at if people understand things in that way. People understand that there are certain expenditure which are avoidable and there are certain projects which are implemented in a very callous way. If proper estimates were prepared and if they were implemented properly.

these would have been eliminated and much of the burden taken off the shoulders of the people. Hence, the preparation of the budget must be done with more care, so that it will be more realistic and more fruitful for the development of our country.

Now I want to deal with the tax structure. It is not a question of paying as much money as the Government wants for the developmental work and for administration; but, actually how is the main question. I will give a few figures. The total annual tax revenue of the Central Government and the State Government increased from Rs. 739 crores in 1951-52 to Rs. 1,371 crores now. Even after making allowance for the high rate of population growth, this means that *per capita* tax load has increased from Rs. 20.5 to Rs. 31.1; an increase of 50 per cent.

What will be the position after the third Five Year Plan? The total of additional taxation put through in the course of a decade—1956-57 to 1965-66 will reach the staggering figure of Rs. 2,862 crores. It is a steep rise from Rs. 739 crores in 1951-52 to Rs. 2,862 crores in 1965-66. That is the prospect of taxation. How is this tax made up? That is another point I would stress.

Everybody knows there are two aspects of taxation-direct taxes and indirect taxes. About direct taxes, many a thing has been said and I do not want to go into details. In 1950-51, the total tax revenue was Rs. 357 crores. In 1961-62 it was Rs. 768 crores, i.e. an increase of Rs. 411 crores. Direct taxes amounted to Rs. 130 crores in 1950-51 and to Rs. 206 crores in 1961-62, i.e. an increase of Rs. 76 crores. Indirect taxes amounted to Rs. 227 crores in 1950-51 and to Rs. 562 crores in 1961-62, i.e. an increase of Rs. 335 crores. What is the proportion of the increased indirect taxes and what is the production of the increase in indirect taxes? Everybody know that indirect tax is the real burden of the common people, who form the majority. This is the burden now and much more is yet to be expected. How can the toiling people bear such a burden?

In his speech, the Finance Minister said that having paid all these taxes, even now the people have money left for meeting all the expenditure, because the price line has been held. It is true that the index of consumer goods has been held. Whether it is held or whether it is holding there, I do not know; but for the last four months, it is remaining at 128. The Pay Commission recommended that if there is an increase of more than 10 points, Government must pay correspondingly more D. A. Now the index has gone up from 115 to 128. Will this increase of 13 points be met by the D. A.? At least after an increase of 10 points, according to the Pay Commission, something must be done. I hope that will be done. *Inter alia*, I am praying for that, so that the Central Government employees may be benefited to that extent.

I will give certain figures to show how the indirect taxes have gone up at a very fast rate. If you compare the figures of collection of taxes for the years 1950-51 and 1961-62 you will know how much burden the people had to bear. In the case of kerosene, it was Rs. 28 lakhs in 1950-51 and Rs. 1,134 lakhs in 1961-62, an increase of Rs. 1,106 lakhs; in the case of sugar, the corresponding figures are Rs. 646 lakhs and Rs. 5,910 lakhs, an increase of Rs. 5,264 lakhs; for matches Rs. 807 lakhs and Rs. 1,803 lakhs an increase of Rs. 996 lakhs; for tobacco Rs. 3,199 lakhs and Rs. 5,977 lakhs, an increase of Rs. 2,778 lakhs; an increase of Rs. 2,778 lakhs; for tea Rs. 336 lakhs and Rs. 963 lakhs, an increase of 627 lakhs; for pepper Rs. 268 lakhs and Rs. 1,117 lakhs, an increase of Rs. 849 lakhs and for vegetable non-essential oil Rs. 29 lakhs and Rs. 1,250 lakhs, an increase of Rs. 1,221 lakhs. If we total up these figures, we will find what a staggering figure it comes to. This is beside the increase

[Shri Warior]

in railway freight which has gone up from Rs. 368 lakhs to Rs. 1250 lakhs.

Who are the people who are paying all these taxes? A Committee appointed by the Government with Shri Jai Prakash Narayan as the chairman discloses that the families whose annual income is less than Rs. 1,000 or Rs. 100 a month constitute 80 per cent of our population. It is from these 80 per cent of the population, especially that portion which lives in the rural areas, that all these taxes must come, as they are the people who are using kerosene, tea and other commodities in larger quantities. For example, kerosene is not used much in the cities. So, we are collecting all these taxes from 80 per cent of our people whose annual income will be less than Rs. 1,.000.

We do not know where the profits of companies and the increase in national income goes. In any case, it is not going to the people. I do not want to take too much of your time by referring to all the details, but I will say this much that the entire economy is not in our hands. The money is going by crores into the pockets of a few families or few hands. In some cases, the profits have scared up as much as 200 per cent and crores and crores of rupees have gone into the pockets of those few people, and those very people are now working not only against the poor people but even against the Government which has helped them in making all this money.

This is the result which we find of the recent elections. And when I am on the elections, I cannot help saying one thing, and that is this, that it is better if the elections to the Assemblies and Lok Sabha are not held simultaneously. Let us separate the Lok Sabha election from the Assembly election or, for that matter, from the Corporation elections. No doubt, it will be very economical if all the elections are held simultaneously, including the panchayat elections, but that will not serve the cause of democracy.

Lastly, I will come to the collection of taxes. There are some honest people in the governmental machinery, especially in the income-tax department. When we see their plight we feel sorry. Whenever any income-tax officer of integrity and honesty catches hold of the real culprit who is evading the tax, that officer comes to grief and is harassed by his superiors in the department. Here I charge even the Central Board of Revenue of being party to it, even though I am prepared to be corrected if it is not so. Now it has come to such a pause that officers of integrity and honesty have no place in this system of administration. I have with me very many instances to substantiate my charge, and I am willing to pass them on to the Finance Minister. These officers certainly need fair treatment at the hands of the Government. Otherwise, they will not have the incentive to work hard, the revenue cannot be collected, the evaders cannot be booked and the people have to suffer much more on that account.

I am glad the Finance Minister has stated in his speech that the collection is more from income-tax and excise. Even then I feel that the evasion is much more now. So, those people who are serving the Government loyally should be rewarded, instead of being made to suffer, for doing their work in an efficient manner. They must receive protection at the hands of the Government so that they will work hard and the finances of the country will improve.

Then I come to the havoc played by red tape, which is hard to break. I am told that the promotion of some of the officers of the Finance Department is still pending with the Union Public Service Commission. How long will their case be kept pending there? On the one hand, we say that we want

new and young blood in the department instead of the old bureaucrats and, on the other, we postpone or keep pending the promotions of young and brilliant officers because of red tape. In the place of the old bureaucrats we want the youngsters of our country who have the knowledge of the national movement, who are fired with enthusiasm and patriotism. They must be given their proper places in the department and they must be given opportunities for promotion to encourage them to work hard for the welfare of this country. But that is not done and even now the Government seems to be in the old rut. I hope the Finance Minister will look into this matter, expedite delayed cases and tighten up the administrative machinery so that our people will suffer less.

**श्री प० ला० बारूपाल** (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

हमारी सरकार ने समाजवादी व्यवस्था के आधार पर देश का निर्माण करने का निश्चय किया है, किन्तु हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार पूंजीवादी है । ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खातीं और भ्रान्ति उत्पन्न करती हैं । इस अवस्था में मैं समझता हूं कि हम शीघ्रता से जो देश का नव-निर्माण करना चाहते हैं, उस में बहुत देर लगेगी । इस लिए अगर देश की वितरण व्यवस्था को समाजवादी आधार पर चलाया जाये, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश शीघ्र प्रगति करेगा ।

इस समय हमारे देश में जो घातक प्रवृत्तियां फैली हुई हैं, अर्थात् रूढ़िवादिता, अन्ध-विशवास और जातीयता आदि, उन को खत्म करना हमारा लक्ष्य रहा है । लेकिन जिन कुप्रवृत्तियों को समाप्त करने का हम ने नारा लगाया, वे जंगल की आग की तरह बढ़ती जा रही हैं और उन में कोई कमी नहीं हुई ।

वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में कुछ नये कर लगाने का जो संकेत किया है, मैं उस का विरोध करता हूं । सरकार डायरेक्ट या इन-डायरेक्ट किसी प्रकार के कर लगाये, लेकिन जिस तरीके से कर लगने चाहिए, वैसे न लगाये जा कर कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगते हैं, जिस से आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग और ग़रीब, बहुत दुखी हैं । आज इस देश का नागरिक तड़प रहा है । वह अपने हाथ-पैर फैला रहा है, लेकिन फिर भी अपने घर की व्यवस्था आसानी से नहीं कर पाता । अपने बच्चों का पेट पालने, शिक्षा की व्यवस्था करने और घर की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इस का अन्दाज़ा दूसरे लोग नहीं कर सकते ।

**15 hrs.**

हम ने बड़े बड़े राजा-महाराजाओं को कई प्रकार की सहूलियतें दीं । इन सहूलियतों का आज राजा लोग नाजायज़ फायदा उठाने लग गये हैं, आज वे राजनीति में सक्रिय भाग लेने लग गये हैं और इस कूद में पड़े हैं । मैं नहीं समझता कि अब उनको प्रिवी पर्स देने की जरूरत शेष रह गई है । उनको जो बड़े बड़े एलाउंस और भत्ते दिये जा रहे हैं, उनमें कमी की जानी चाहिए और जो पैसा बचे वह देश के निर्माण मे खर्च किया जाना चाहिए । इनको आज इतना पैसा मिल रहा है कि वे इसको सम्भाल नहीं पा रहे हैं और उसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं । आज उनके घरों के अन्दर जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, वे विदेशों से आती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जो हमारा पैसा है वह विदेशों को जाता है । हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहना चाहिए ।

[श्री प० ला० बारूपाल]

किसी माननीय सदस्य ने यहां हाउस टैक्स लगाने की बात कही है । अगर ऐसा किया गया तो जो गरीब लोग किराये के मकानों में रहते हैं उनको ही यह टैक्स किसी न किसी रूप में अदा करना पड़ेगा । सरकार जब दूसरी चीजों का नियंत्रण करती है तो ये जो बड़े बड़े भवन हैं या ये जो फालतू मकान पड़े हुए हैं, इनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती है, इनको अपने अन्तर्गत क्यों नहीं लाती है । लोगों को आज उचित किरायों पर मकान नहीं मिल रहे हैं और मकानों की कमी महसूस की जा रही हैं लेकिन दूसरी तरफ हम पाते हैं कि मकान फालतू पड़े हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इनको सरकार अपने अधिकार में ले ले ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वकील लोग जोकि एक एक बार में ढाई हजार, या तीन हजार या दो हजार बतौर फीस के ले लेते हैं उन पर भी कर लगना चाहिए ।

**श्री रघुनाथ सिंह** : वकीलों पर टैक्स है ।

**श्री प० ला० बारूपाल** : वे टैक्स छिपा करके रखते हैं, वे हम से और आप से ज्यादा होशियार हैं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डाक्टरों की जो कमाई है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए । जिस जिस हिसाब से वे मरीजों से फीस लेते हैं और जितने वे योग्य होते हैं, उसी प्रकार से इन पर भी टैक्स लगना चाहिए ।

मैं ने कहीं पर भी आपके बजट में फर्नीचर पर टैक्स लगाया हो, ऐसा नहीं पाया है । फर्नीचर बड़े बड़े लोग खरीदते हैं अमीर लोग खरीदते हैं और इस पर भी टैक्स लगना चाहिए ।

बहुत से लोगों की समझ में यह बात नहीं आई है कि क्यों हमारी सरकार मठों और मंदिरों की जो सम्पत्ति है, उसमें हस्तक्षेप करने से डरती है । मंदिरों और मठों में जो लोग हैं वे ही आज आम जनता को गुमराह कर रहे हैं । पिछले दिनों अष्टग्रहों की बड़ी चर्चा थी और बहुत बड़ा बवण्डर मचा था । इस सब के लिये ये मंदिर और मठ ही जिम्मेदार थे । इनके पास करोड़ों और अरबों रुपयों की सम्पत्ति है । क्यों नहीं सरकार इस सम्पत्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में करती है । कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और हम धार्मिक मामलों मे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । लेकिन सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ये लोग जनता को गुमराह न कर सकें । गंगानगर की मिसाल मेरे सामने है । दस तहसीलों से मैं चुन कर आया हूं । गंगानगर में ६२,००० रुपये नकद और खीर पूरी अलग से हर रोज इन अष्टग्रहों के सिलसिले मे उड़ते रहे हैं और यहां पर श्रमहीन प्रार्थनाएं होती रही हैं । कितना लोगों का समय बरबाद हुआ और कितना धन लगा इसका अगर आप मूल्यांकन करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत भारी राशि व्यर्थ में गई । इस राशि का उपयोग हमारी योजना को कार्यान्वित करने में किया जा सकता था । जो झूठी अफवाहें फैलाई गईं उनको रोकने में हमारी सरकार असमर्थ रही । मैंने सुना है कि किसी दूसरे यश में इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा करने की जब किसी ने कोशिश की तो न सिर्फ उसको जेल में डाल दिया गया बल्कि जहां तक मुझे बताया गया है उसको शूट कर दिया गया । कितना नुकसान इस दौरान में देश का हुआ है इसका आपको अंदाजा होना चाहिए । सरकार जब तक इस तरह की चीजों पर नियंत्रण नहीं करेगी, हमारे देश का भला नहीं होगा ।

आज देश में जो काम हो रहे हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं । लेकिन मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि कई काम हैं

जो अधूरे पड़े हुए हैं और आप को चाहिए कि आप उनको पूरा करें ।

अब मैं हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । हिन्दी की पिछले दस वर्षों में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी नहीं हुई है । पैसा खर्च करने के बावजूद भी आज देखने में आता है कि हिन्दी की उपेक्षा की जाती है ।

15·04 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

हिन्दी के बारे में हमें बहुत गम्भीरता से सोचना होगा । आज भी हम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाये हुए हैं । मैं समझता हूं कि अगर हिन्दी की शिक्षा का माध्यम बना दिया जाये तो जो अहिन्दी भाषा भाषी हैं उनको जितनी आज अंग्रेजी पढ़ने में तकलीफ होती है उससे कम ही तकलीफ अंग्रेजी भाषी को होगी । जब आपने हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा हिन्दी को माना है तो हिन्दी की उपेक्षा किसी भी तरह से आपको नहीं करनी चाहिए ।

पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातों का जिक्र किया है, मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनको कहते हुए मुझे दर्द का अनुभव होता है । जिस तरह से आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती है, वह शोभा की बात नहीं है । हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं । लेकिन संविधान के अन्दर कुछ जातियों को विशेष रियायतें दी गई हैं । लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी ये रियायतें मिल गई हैं जोकि इनके अधिकारी नहीं थे । जो अस्पृश्य हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन्हीं को ये रियायतें मिलनी चाहियें । जब यहां ब्रिटिश साम्राज्य था और राजाओं का राज्य था तो हम लोग उन्हीं लोगों के गुलाम थे, अछूत कहलाते थे । लेकिन अब भीख बंटने का वक्त आया तो कई लोगों ने अपने आप को हरिजन लिखाना शुरू कर दिया और जो सहूलियतें दी गई थीं उनका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया । जो दूसरे हरिजन लोग थे, उन्होंने कहा कि कल तक तो ये हरिजन नहीं थे, हिन्दू कसाई थे उसके हाथ का गोश्त राजा खाते थे । चमार की जूती को राजा महाराजा तो नहीं पहनते थे लेकिन उस मोची की जूती को राजा महाराजा पहनते थे, जिनको मंदिर में जाने का अधिकार था, कुंए पर पानी भरने का अधिकार था लेकिन इस बहती गंगा में उन लोगों का नैतिक पतन हुआ और सभी ने अपने आपको शैड्यूल्ड कास्ट लिखाना शुरू कर दिया और नाजायज तरीके से फायदा उठाया । इसका नतीजा यह हुआ कि जो अछूत थे, उनको उनसे ईर्ष्या होने लग गई । वे कहने लग गये कि कल तक तो ये हम से घृणा करते थे आज हमारे बराबर आ कर खड़े हो गये हैं क्योंकि आज कुछ सुविधायें मिल गई हैं । इसलिए इसका नतीजा यह हुआ कि अछूतों ने उनको सहयोग देना बन्द कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि जो इन सहूलियतों को पाने का अधिकारी है उसको ही ये सहूलियतें दी जानी चाहिए दूसरों को नहीं । यह भी कहा जाता है कि कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जब मौके पर एफीडेविट देने का सवाल आता है तो जो सुनार होता है या अदर बैक्वर्ड क्लासिज का आदमी यहां तक की कास्ट हिन्दू ब्राह्मण होता है वह भी वकील की सहायता से शड्यूल्ड कास्ट का सार्टिफिकेट ले आता है । नौकरी तो मिलनी चाहिए शड्यूल्ड कास्ट को लेकिन उसको न मिल कर किसी और को ही मिल जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि जो हकदार है उसको वह चीज नहीं मिलता है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की चोर्जों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए ।

बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इस वास्ते मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । मारे

[श्री प० ला० बारूपाल]

वर्मा जी और दूसरे माननीय सदस्य बोलने के लिए तयारी कर रहे हैं, इस वास्ते मैं दो चार मिनट में समाप्त कर दूंगा । मैंने देखा है कि सरकारी डिपार्टमैंट्स के द्वारा कई चीजें छपवाई जाती हैं, कितना ही लिटरेचर छपवाया जाता है, जो किसी काम नहीं आता है, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल निकम्मा होता है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । कोई मम्बर नहीं पढ़ता है, छः आने के हिसाब से रद्दी में उसको बेच दिया जाता है । बढ़िया बढ़िया आर्ट पेपर पर वह छपवाया जाता है, कैटालाग बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, हजारो और लाखों रुपया खर्च करते हैं और यह सब बरबाद जाता है, किसी काम में नहीं आता है । मैं आपको बताऊं कि एक एक मम्बर को तीन तीन, चार चार और पांच पांच डायरियां दी जाती हैं जब कि व एक डायरी भी रखने में असमर्थ होते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत है । मैं समझता हूं कि इसके अन्दर भी कोरप्सन की गुंजाइश है, पसा खान की गुंजाइश है । एक हजार छपवात हैं और एक बिन्दी लगा कर कह देत हैं कि दस हजार छपवाई है, एक हजार की पेमेंट कर देते हैं और बाकी जो नौ हजार का पसा होता है वह फिफटी फिफटी के हिसाब से बांट लिया जाता है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली में मैं एक प्रेस में बैठा था । एक एंटी कोरप्शन डिपार्टमेंट है जो शिमला में है और उसके हमारे आफिसर साहब वहां आए और उन्होंने कहा कि बीस हजार पोस्टर भ्रष्टाचार निवारण के बारे में छपवाने हैं लेकिन साफ बात यह है कि पांच हजार छाप दीजिए और बीस हजार का बिल दे दीजिए और जो बाकी पन्द्रह हजार पोस्टर हैं, वे न छापिए और उनके पसे आधे आधे बांट लीजिए । हमारे प्रधान मंत्री जो नहीं मानत हैं कि यहां कोरप्शन है, हमारे वित्त मंत्री श्री देसाई जी नहीं मानते हैं कि कोरप्शन है और कहते हैं कि यह सब बकवास है, उनको अब कैसे बताया जाए कि करप्शन है । इस भ्रष्टाचार को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं । सीमा पर बहुत ज्यादा स्मगलिंग होता है लेकिन उसकी तरफ से आंखें बन्द कर ली जाती हैं । लोग पकड़े भी जाते हैं, मुकदमें भी चलते हैं, कौन आदमी किस तरोके से करता है, यह भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी सोना पीतल में बदल जाता है और पीतल का पता नहीं चलता है कि वह कहां चला गया । यह रोजमर्रा होता है और रोजमर्रा की ये कहानियां हैं । ये सब चीजें हैं जिन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए ।

मैं मानता हूं कि भौतिक तरक्की हमारे देश में काफी हुई है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी एक कटु सत्य है कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से मारेलेटी की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से हमारा देश नीचे गया है । हमारे देश में नहरें तो बन गई हैं, खड्डे भी भरे गए हैं, सड़कें भी बन गई हैं मगर मनुष्य बनाने में हमारी सरकार असमर्थ रही है, आदमी नहीं बना सके हैं । अगर हम आदमी नहीं बना सकेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकेगा । एक दोहा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं :

गोधन गजधन राजधन और रत्न धन खान ।
जब नहीं है सन्तोष मन सब धन धूल समान ।।

आज को इतनी बड़ी चीजो का उपभोग कौन करेगा जब मनुष्य करप्ट हो जायेंगे, भ्रष्ट हो जायेंगे ? सब जगहों पर असन्तोष फैलता जाता है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें मैं ने कहीं हैं उन पर ठीक तरह से विचार किय जाय । मेरे पास कहने को बहुत है लेकिन यहां शायद कुछ लोग समझते हैं कि मैं फालतू बोल कर उन का समय खाये जा रहा

हूं । फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर ठीक तरह से विचार किया जाय । इस का पता लगाया जाय कि कौन से लोग अपराधी हैं, कौन लोग अपराध करते हैं और कौन लोग काम ठीक तरीके से करते हैं । हमारे दफ्तरों के अन्दर जितने बड़े बड़े अफसर हैं जो बड़ी बड़ी तन्ख्वावं लेते हैं, वे ठीक समय से आते हैं या नहीं, ठीक समय से जाते है या नहीं, वे ठीक ढंग से काम करते हैं या नहीं आज इस को देखने की जरूरत है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं । इसी तरह से मजदूरो पर किसी का कंट्रोल नहीं है । मजदूर भी खुल खेलते हैं ।

अफसर काम नहीं करते हैं और बैठ कर सरकार की आलोचना करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उन का मुंह कितना खुल गया है, जो चाहते हैं कह डालते हैं, तो नीचे के लोग उन की बातों को सुनते हैं । व भी कहते हैं कि जब उन के अफसर यह बातें कह सकते हैं तो वे क्यों नहीं कह सकते ? इस बात के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये ।

मैं ने महसूस किया है इन दस सालों के अन्दर कि हमारा देश डिमाक्रेसी के लायक नहीं था । जिन के हाथों में हम ने बागडोर दे दी है वे अफसरों को आज्ञा देते हैं और अफसर लोग गांवों में जा कर लोगों पर अपना हुक्म चलाते हैं । दूसरी तरफ गांवों वाले इतने लायक नहीं हैं जो कि उन अफसरों पर कंट्रोल कर सकें । वे गांवों की योजनाओं को ठीक ढंग से बना सकें और उन को पूरा कर सकें, यह किस तरीके से सम्भव हो सकता है ? और किस तरीके से मुल्क के अन्दर तरक्की होगी । यह कई बातें ऐसी हैं जिन को आप को ही गम्भीरता से सोचना है और गम्भीरता से सोच कर एक नया मोड़ मुल्क के अन्दर लाना होगा । मुझे पंडित जी के शब्द याद हैं कि अगर एक मिनट के लिये एक आदमी काम नहीं करता तो वह देश को एक मिनट पीछे रखता है । आप देखिये कि सारे मिनट मिला कर कितने आदमी काम करते हैं और कितने फालतू बैठे रहते हैं ।

इसी तरह से भिखमंगों का सवाल है । भिखमंगों को रोकने में आप असमर्थ हैं । आज बेकारी देश में बढ़ गई है । आज लोग दर दर की ठोकरे खाते फिरते हैं और परेशान होते हैं । इस के लिये आप को बहुत काम करने की जरूरत है क्योंकि आप इस समस्या को हल करने में असमर्थ रहे हैं ।

मुझे इतनी बातें कहने के लिये आप माफ करेंगे, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वह मेरे हृदय को छूने वाली चीजें हैं । मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैं न कही हैं उन पर आप ध्यान देंगे । अभी यहां कहा जाता है कि देश में कास्टीज्म फैल रहा है । लेकिन यहां थोड़े से आदमी हैं जो कि कास्टीज्म फैलाते हैं । बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हरिजनों को रुपया दे कर चुनाव में अलग से खड़ा किया क्योंकि उन को वोट लेना था । हरिजन बेचारे अबोध, असमर्थ और अनभिज्ञ हैं, वे पढ़े लिखे नहीं हैं । वे सोचते हैं कि जब पढ़े लिखे आदमी एम० पी० बन सकते हैं तो वे क्यों नहीं बन सकते हैं । यह उन का अधिकार है जो कि कांस्टिट्यूशनल राइट है । हर आदमी अपना विचार स्वातंत्रय रखता है, हर आदमी को अपनी प्रगति के लिये समान अवसर दिया जाता है । क्या हुकूमत ने कभी इस बात की जांच करवाई कि उन गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आ गया । क्या कभी उन्होंने एन्क्वायरी करवाई कि जिन हरिजन के पास खाने के लिये रोटी नहीं थी, उस को १० हजार रुपये किस कम्पनी ने दिये, किस बनियें ने दिये या किस लीडर ने दिये ? यह बात नहीं है कि सिर्फ हरिजनों में ही कास्टीज्म है । कास्टीज्म फैलाने वाले हमारे हाई कास्ट वाले हैं जो कि हरिजनों को रुपये दे कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं । उन को आपस में लड़वाने के लिये वे पैसा देते हैं । मैं कहना

[Shri Naldurgkar]

our country. Therefore, it is better that a sort of harmony should be maintained between all States and between all sections of the people, because it is only harmony that can rid us of all these vices. If the Government take steps in that direction, I am of the view that there will be no further disputes concerning border issues or any other issues which are prejudicial to the harmonious progress of our country.

**Shri D. C. Sharma:** This is an interim Budget that we are discussing and, therefore, there is an air of unreality about whatever we say. I do not know what is going to be in store for us when the real Budget is presented in the next Session when the Third Lok Sabha sits for the first time. I do not know what surprises our Finance Minister will have in store for us. I cannot also imagine what concessions he will have to give us. I cannot foresee what he will do to make the plans as successful as they are today or more successful than they have been before. All these are matters of speculation.

But one thing is sure, that our two Plans have gone off very well. Judging by the experience we have got of the working of these two Plans, I can say with some amount of certainty that our Third Plan will also succeed. And the success of our Third Plan would mean a spurt in the national economy all along the line. Already we know that there has been an upward trend so far as our national income is concerned. We also know that so far as the *per capita* income is concerned, we have registered some kind of advance. All these things show the health and soundness of our economy for which I think our Finance Minister deserves thanks not only from us but also from the whole nation.

There is one thing which is very disturbing, and that is, how the national income is being distributed. While rising to speak on the interim Budget, I cannot forget the elections that I have fought and my other hon. friends have fought. What was our stock in trade when we were delivering our election speeches? I think our main stock in trade was our Plans, the First Five Year Plan and the Second Five Year Plan. We also tried to win the votes of the people on the score of the Third Plan that we launched a little earlier than the elections.

Now, people ask us very naturally, and this is also the main brunt of the criticism of the opposition parties, how the money has been distributed. I do not know how many categories of income distribution our Finance Ministry has. I do not know what brackets of income they take into account when they are going to think of the distribution of national income. But I would say that so far as the criticism of the opposition parties goes, they were very vocal and very insistent in saying that the Plan has made the rich richer and the poor poorer.

I do not think there is much substance or truth in what they said. But the fact of the matter this is. If you look at the map of any district in the whole of India you will find that that district consists of 3 types of localities. There are what I call cities. I feel that these Plans have definitely contributed to the prosperity of those cities. The cities show a great deal of improvement all along the line. Of course, there may be slums here and there. There may be a few places which need looking into everywhere. But, I think, the cities of India are doing very well.

I want you to look only at the map of Delhi city. What was this Delhi city in 1946 or in 1947 before India became independent; and what is Delhi city today? Anyone who goes round this Delhi city or New Delhi city will come to the conclusion that India is very prosperous because Delhi city shows so many signs of prosperity.

हूं । फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर ठीक तरह से विचार किया जाय । इस का पता लगाया जाय कि कौन से लोग अपराधी हैं, कौन लोग अपराध करते हैं और कौन लोग काम ठीक तरीके से करते हैं । हमारे दफ्तरों के अन्दर जितने बड़े बड़े अफसर हैं जो बड़ी बड़ी तन्ख्वावं लेते हैं, वे ठीक समय से आते हैं या नहीं, ठीक समय से जाते हैं या नहीं, वे ठीक ढंग से काम करते हैं या नहीं आज इस को देखने की जरूरत है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं । इसी तरह से मजदूरों पर किसी का कंट्रोल नहीं है । मजदूर भी खुल खेलते हैं ।

अफसर काम नहीं करते हैं और बैठ कर सरकार की आलोचना करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उन का मुंह कितना खुल गया है, जो चाहते हैं कह डालते हैं, तो नीचे के लोग उन की बातों को सुनते हैं । व भी कहते हैं कि जब उन के अफसर यह बातें कह सकते हैं तो वे क्यों नहीं कह सकते ? इस बात के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये ।

मैं ने महसूस किया है इन दस सालों के अन्दर कि हमारा देश डिमाक्रेसी के लायक नहीं था । जिन के हाथों में हम ने बागडोर दे दी है वे अफसरों को आज्ञा देते हैं और अफसर लोग गांवों में जा कर लोगों पर अपना हुक्म चलाते हैं । दूसरी तरफ गांवों वाले इतने लायक नहीं हैं जो कि उन अफसरों पर कंट्रोल कर सकें । वे गांवों की योजनाओं को ठीक ढंग से बना सकें और उन को पूरा कर सकें, यह किस तरीके से सम्भव हो सकता है ? और किस तरीके से मुल्क के अन्दर तरक्की होगी । यह कई बातें ऐसी हैं जिन को आप को ही गम्भीरता से सोचना है और गम्भीरता से सोच कर एक नया मोड़ मुल्क के अन्दर लाना होगा । मुझे पंडित जी के शब्द याद हैं कि अगर एक मिनट के लिये एक आदमी काम नहीं करता तो वह देश को एक मिनट पीछे रखता है । आप देखिये कि सारे मिनट मिला कर कितने आदमी काम करते हैं और कितने फालतू बैठे रहते हैं ।

इसी तरह से भिखमंगों का सवाल है । भिखमंगों को रोकने में आप असमर्थ हैं । आज बेकारी देश में बढ़ गई है । आज लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं और परेशान होते हैं । इस के लिये आप को बहुत काम करने की जरूरत है क्योंकि आप इस समस्या को हल करने में असमर्थ रहे हैं ।

मुझे इतनी बातें कहने के लिये आप माफ करेंगे, लेकिन जो कुछ मैं ने कहा है वह मेरे हृदय को छूने वाली चीजें हैं । मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैं न कही हैं उन पर आप ध्यान देंगे । अभी यहां कहा जाता है कि देश में कास्टीज्म फैल रहा है । लेकिन यहां थोड़े से आदमी हैं जो कि कास्टीज्म फैलाते हैं । बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हरिजनों को रुपया दे कर चुनाव में अलग से खड़ा किया क्योंकि उन को वोट लेना था । हरिजन बेचारे अबोध, असमर्थ और अनभिज्ञ हैं, वे पढ़े लिखे नहीं हैं । वे सोचते हैं कि जब पढ़े लिखे आदमी एम० पी० बन सकते हैं तो वे क्यों नहीं बन सकते हैं । यह उन का अधिकार है जो कि कांस्टिट्यूशनल राइट है । हर आदमी अपना विचार स्वातंत्रय रखता है, हर आदमी को अपनी प्रगति के लिये समान अवसर दिया जाता है । क्या हुकूमत ने कभी इस बात की जांच करवाई कि उन गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आ गया । क्या कभी उन्होंने एन्क्वायरी करवाई कि जिन हरिजन के पास खाने के लिये रोटी नहीं थी, उस को १० हजार रुपये किस कम्पनी ने दिये, किस बनिये ने दिये या किस लीडर ने दिये ? यह बात नहीं है कि सिर्फ हरिजनों में ही कास्टीज्म है । कास्टीज्म फैलाने वाले हमारे हाई कास्ट वाले हैं जो कि हरिजनों को रुपये दे कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं । उन को आपस में लड़वाने के लिये वे पैसा देते हैं । मैं कहना

[Shri Naldurgkar]

our country. Therefore, it is better that a sort of harmony should be maintained between all States and between all sections of the people, because it is only harmony that can rid us of all these vices. If the Government take steps in that direction, I am of the view that there will be no further disputes concerning border issues or any other issues which are prejudicial to the harmonious progress of our country.

**Shri D. C. Sharma:** This is an interim Budget that we are discussing and, therefore, there is an air of unreality about whatever we say. I do not know what is going to be in store for us when the real Budget is presented in the next Session when the Third Lok Sabha sits for the first time. I do not know what surprises our Finance Minister will have in store for us. I cannot also imagine what concessions he will have to give us. I cannot foresee what he will do to make the plans as successful as they are today or more successful than they have been before. All these are matters of speculation.

But one thing is sure, that our two Plans have gone off very well. Judging by the experience we have got of the working of these two Plans, I can say with some amount of certainty that our Third Plan will also succeed. And the success of our Third Plan would mean a spurt in the national economy all along the line. Already we know that there has been an upward trend so far as our national income is concerned. We also know that so far as the *per capita* income is concerned, we have registered some kind of advance. All these things show the health and soundness of our economy for which I think our Finance Minister deserves thanks not only from us but also from the whole nation.

There is one thing which is very disturbing, and that is, how the national income is being distributed. While rising to speak on the interim Budget, I cannot forget the elections that I have fought and my other hon. friends have fought. What was our stock in trade when we were delivering our election speeches? I think our main stock in trade was our Plans, the First Five Year Plan and the Second Five Year Plan. We also tried to win the votes of the people on the score of the Third Plan that we launched a little earlier than the elections.

Now, people ask us very naturally, and this is also the main brunt of the criticism of the opposition parties, how the money has been distributed. I do not know how many categories of income distribution our Finance Ministry has. I do not know what brackets of income they take into account when they are going to think of the distribution of national income. But I would say that so far as the criticism of the opposition parties goes, they were very vocal and very insistent in saying that the Plan has made the rich richer and the poor poorer.

I do not think there is much substance or truth in what they said. But the fact of the matter this is. If you look at the map of any district in the whole of India you will find that that district consists of 3 types of localities. There are what I call cities. I feel that these Plans have definitely contributed to the prosperity of those cities. The cities show a great deal of improvement all along the line. Of course, there may be slums here and there. There may be a few places which need looking into everywhere. But, I think, the cities of India are doing very well.

I want you to look only at the map of Delhi city. What was this Delhi city in 1946 or in 1947 before India became independent; and what is Delhi city today? Anyone who goes round this Delhi city or New Delhi city will come to the conclusion that India is very prosperous because Delhi city shows so many signs of prosperity.

Then, I come to what are called towns. By a town I mean places where the population is between 10,000 and 50,000 or something like that. When I look at the condition of these towns, I say that with some amount of responsibility, these towns have not shown that sign of getting along as the big cities have shown. I do not want to generalise from my experience of my own constituency. But I can say without fear of contradiction that the small town is having a bad time in our eonomy today. There was a time when the small town was flourishing. I go to some of these small towns and I find that the economy of those towns has been disrupted. The avenues of trade and industry have dried up. The channels of money-making have become less and less productive. So, the small town, I should say, has not done very well under these Plans that we have had.

Then, I come to the villages. I think there is some improvement in the village. There is no doubt about that. The villages, on account of the Panchayati Raj that we have set up, on account of other welfare agenies that we have brought into being, show some signs of improvement But still, the improvement that is there is very very insifgnificant when compared with the improvement that we find in some of these big cities. Of course, these big cities have also their own problems. I do not deny that.

Therefore, I ask myself this question. Are our Plans going to represent balanced development of our country or are they going to create greater disparities between city and city, between town and town and between a city, a town and a village? I think this is a very pertinent question that I have to put myself. I am not asking this question of the Finance Minister. He will have an answer for it as he has an answer for every question that I can put him. But, I ask myself this question. Is it not a fact that our development has not been in accordance with the needs of the different sections of the population, the different localities? When I want to give an answer to this question I do not feel very happy.

The Government of India has appointed a committee to see how the national income has been distributed. I do not know how long we will have to wait for the report of that committee. Perhaps, we will have the report of that committee at a time when the whole report has become obsolete. Perhaps, we will have the report at a time when the findings of that committee will have no relevancy to the reality that we will have to face at the time of its publication. We have waited too long for that report and our patience has been exhausted. But, whether that report comes or does not come out, I feel that if our planning is to acquire an air of reality than it has today and if our planning is to go to the bosom of men who are working these plans and who are going to be benefited by these plans, the Finance Minister will be doing a great deal of national service and will be blazing a new trail in our Indian economy if he tries to have an assessment of the working of these plans at the district level.

Every district should bring forward an account of what the Plan has done for the district and what the Plan has not done for the district; what the Plan has done for some cities and what the Plan has done for some towns and what the Plan has done for some villages. I do not say that the Plan has done nothing. When I go to some of the villages I find big houses; I find people better clad; I find people going about with a greater air of confidence. I see all these things. But, all the same, I cannot avoid the impression that our development on account of these Plans has been, in a way lopsided. We have given more to the cities than they deserve. We have given less to the towns than they want; and we have not given to the villages as much as they need. That is the biggest thing that I will say about these Plans.

What is the result? The result is that a very sizable section of our

[Shri D. C. Sharma]

ladies were taken to holy places like temples, etc., and were made to swear on holy books that they would not vote for the Congress candidate? Do you know that, Sir?

**An Hon. Member:** Voted for whom?

**Shri D. C. Sharma:** I know how the hon. Member got the votes. Let him be quiet. I am addressing the Chair. I say, Sir, that ladies were taken to temples and were asked not to vote for the Congress candidate because he was the enemy! Many things were asked to be done. Much is being made of the election of the Chief Minister of my State. He has won by 34 votes, but he has won. It does not matter by how many votes. He has won in a fair and impartial and free election. If there are any stories about his success by Opposition Parties, I think we should not give any credence to them. Every vote is scrutinised by the counting agents; they have the eyes of eagles. Nothing can escape them. Therefore, these things are being said, but then, what I want to submit respectfully is that all the clauses of the amended Representation of the People Act, which was passed here, and in which the parties were asked not to make any appeals in the way I mentioned earlier, have been violated. It is up to us to see that these things do not happen in the future and that people do not resort to such things. Where is secularism when these rightist parties come to fight us? Where is democracy when they want to win votes against us? All these things are thrown to the winds.

It has been said that posters should be first sent to the District Magistrates as well as the pamphlets. All these things are there in the law. But I submit that posters have been published—I do not want to tell you what kind of posters were published—and pamphlets have been written—and I do not want to tell you what kind of pamphlets were written—to bring into bad odour some of the parties including the Congress Party. I would request the parties to see to it that the elections are fought in a clean way, and I say this not only to the Opposition Party but to everyone. We should have clean elections in the future—elections where the honour of our sisters and mothers is not called into question; where the honour of our ancestors is not called into question; where all kinds of things are not trotted out in order to win the elections.

I submit that if anything is being said about the Jammu and Kashmir election, it is a travesty of facts. Jammu and Kashmir elections have been fought as well and in as fair and impartial a manner as the elections in other parts of India, and it does not behove anyone to question the fairness of the elections in Jammu and Kashmir.

There is one more point to which I want to make a reference before I sit down, and that is about Jammu and Kashmir. Somehow or other, I have some sentimental ties with Jammu and Kashmir. The first ten years of my life were spent in Jammu and Kashmir. My mother came from the State of Jammu and Kashmir. So, I have some sentimental ties with that State. When I was a teacher, I used to teach As You Like It. In it, there was a sentence in which it was said: "To him who has much will be given more and to him who has little will be given less". That is what has happened in the case of Jammu and Kashmir. The third Finance Commission has been very, very just in its findings on the whole, but it has not dealt with Kashmir in a very fine way. I think what the Finance Commission does not do can be done by the Finance Minister. I think that the Jammu and Kashmir State, which is our key State, where we are having secularism and all kind of thing, must be given a fair deal by the Finance Minister so that whatever

Then, I come to what are called towns. By a town I mean places where the population is between 10,000 and 50,000 or something like that. When I look at the condition of these towns, I say that with some amount of responsibility, these towns have not shown that sign of getting along as the big cities have shown. I do not want to generalise from my experience of my own constituency. But I can say without fear of contradiction that the small town is having a bad time in our eonomy today. There was a time when the small town was flourishing. I go to some of these small towns and I find that the economy of those towns has been disrupted. The avenues of trade and industry have dried up. The channels of money-making have become less and less productive. So, the small town, I should say, has not done very well under these Plans that we have had.

Then, I come to the villages. I think there is some improvement in the village. There is no doubt about that. The villages, on account of the Panchayati Raj that we have set up, on account of other welfare agenies that we have brought into being, show some signs of improvement But, still, the improvement that is there is very very insifgnificant when compared with the improvement that we find in some of these big cities. Of course, these big cities have also their own problems. I do not deny that.

Therefore, I ask myself this question. Are our Plans going to represent balanced development of our country or are they going to create greater disparities between city and city, between town and town and between a city, a town and a village? I think this is a very pertinent question that I have to put myself. I am not asking this question of the Finance Minister. He will have an answer for it as he has an answer for every question that I can put him. But, I ask myself this question. Is it not a fact that our development has not been in accordance with the needs of the different sections of the population, the different localities? When I want to give an answer to this question I do not feel very happy.

The Government of India has appointed a committee to see how the national income has been distributed. I do not know how long we will have to wait for the report of that committee. Perhaps, we will have the report of that committee at a time when the whole report has become obsolete. Perhaps, we will have the report at a time when the findings of that committee will have no relevancy to the reality that we will have to face at the time of its publication. We have waited too long for that report and our patience has been exhausted. But, whether that report comes or does not come out, I feel that if our planning is to acquire an air of reality than it has today and if our planning is to go to the bosom of men who are working these plans and who are going to be benefited by these plans, the Finance Minister will be doing a great deal of national service and will be blazing a new trail in our Indian economy if he tries to have an assessment of the working of these plans at the district level.

Every district should bring forward an account of what the Plan has done for the district and what the Plan has not done for the district; what the Plan has done for some cities and what the Plan has done for some towns and what the Plan has done for some villages. I do not say that the Plan has done nothing. When I go to some of the villages I find big houses; I find people better clad; I find people going about with a greater air of confidence. I see all these things. But, all the same, I cannot avoid the impression that our development on account of these Plans has been, in a way lopsided. We have given more to the cities than they deserve. We have given less to the towns than they want; and we have not given to the villages as much as they need. That is the biggest thing that I will say about these Plans.

What is the result? The result is that a very sizable section of our

[Shri D. C. Sharma]

ladies were taken to holy places like temples, etc., and were made to swear on holy books that they would not vote for the Congress candidate? Do you know that, Sir?

**An Hon. Member:** Voted for whom?

**Shri D. C. Sharma:** I know how the hon. Member got the votes. Let him be quiet. I am addressing the Chair. I say, Sir, that ladies were taken to temples and were asked not to vote for the Congress candidate because he was the enemy! Many things were asked to be done. Much is being made of the election of the Chief Minister of my State. He has won by 34 votes, but he has won. It does not matter by how many votes. He has won in a fair and impartial and free election. If there are any stories about his success by Opposition Parties, I think we should not give any credence to them. Every vote is scrutinised by the counting agents; they have the eyes of eagles. Nothing can escape them. Therefore, these things are being said, but then, what I want to submit respectfully is that all the clauses of the amended Representation of the People Act, which was passed here, and in which the parties were asked not to make any appeals in the way I mentioned earlier, have been violated. It is up to us to see that these things do not happen in the future and that people do not resort to such things. Where is secularism when these rightist parties come to fight us? Where is democracy when they want to win votes against us? All these things are thrown to the winds.

It has been said that posters should be first sent to the District Magistrates as well as the pamphlets. All these things are there in the law. But I submit that posters have been published—I do not want to tell you what kind of posters were published—and pamphlets have been written—and I do not want to tell you what kind of pamphlets were written—to bring into bad odour some of the parties including the Congress Party. I would request the parties to see to it that the elections are fought in a clean way, and I say this not only to the Opposition Party but to everyone. We should have clean elections in the future—elections where the honour of our sisters and mothers is not called into question; where the honour of our ancestors is not called into question; where all kinds of things are not trotted out in order to win the elections.

I submit that if anything is being said about the Jammu and Kashmir election, it is a travesty of facts. Jammu and Kashmir elections have been fought as well and in as fair and impartial a manner as the elections in other parts of India, and it does not behove anyone to question the fairness of the elections in Jammu and Kashmir.

There is one more point to which I want to make a reference before I sit down, and that is about Jammu and Kashmir. Somehow or other, I have some sentimental ties with Jammu and Kashmir. The first ten years of my life were spent in Jammu and Kashmir. My mother came from the State of Jammu and Kashmir. So, I have some sentimental ties with that State. When I was a teacher, I used to teach As You Like It. In it, there was a sentence in which it was said: "To him who has much will be given more and to him who has little will be given less". That is what has happened in the case of Jammu and Kashmir. The third Finance Commission has been very, very just in its findings on the whole, but it has not dealt with Kashmir in a very fine way. I think what the Finance Commission does not do can be done by the Finance Minister. I think that the Jammu and Kashmir State, which is our key State, where we are having secularism and all kind of thing, must be given a fair deal by the Finance Minister so that whatever

they have lost on account of the Finance Commission is made good in an ample measure by the Finance Minister.

Mention was made about the roads. May I tell you that I myself have gone or travelled by the Bhimbher-Shopian road twice? Therefore, that road also has some association for me, and if anybody says that that road should not be built, I would say that that gentleman does not know the beauty of that road. I have trod every inch of that road on foot. Of course, I used to go by that road when I was a little boy. In 1943-45, I went on foot along that road, and I have some ties with that road. I think that one of the wise things that the Jammu and Kashmir State is doing is to rebuild that road. I agree with Shri Raghunath Singh that the Kangra-Kishtwar road should also be built. We want so many other alternative routes to Kashmir. Kashmir is a very sensitive point, so far as defence goes....

**16 hrs.**

**Shri Tyagi** (Dehra Dun): How would the hon. Member react to the suggestion that the Kashmir State must be brought into line with the other States constitutionally, so that it may be at par with U.P. and the other States?

**Shri D. C. Sharma:** That is what they also want. I think that will be done and that is being done. I thank the Finance Minister for being generous to the State. This shows how alert he is to our national needs, how vigilant he is about the defence of our county and how in spite of the fact that other things are also necessary, he has been so particular about defence.

So far as defence is concerned, of course, defence should be there in terms of Army, Navy and Air Force; I do not deny that our defence is well looked after these days. But when we talk of defence, we should talk of border States, border districts and border areas. Unless you look upon this as an integrated whole, I think the whole planning for development will not be very fruitful. For instance, take Punjab. It is a border State. Rajasthan is a border State. Gurdaspur is a border district which connects Punjab with Jammu and Kashmir; it is the gateway to Jammu and Kashmir.

Planning requires that you do not always adopt the rule of the thumb methods in the allocation of money. Planning should have a little imagination. When you employ a little imagination, you will find that the border States like Rajasthan and Punjab and border districts like Gurdaspur and Amritsar deserve special-nation treatment at the hands of the Finance Minister. I have been told about the inaccessible areas committee, hill areas committee, etc. We have so many committees and I do not object to them. But I am doubtful about the advantages which will flow from the committees to these areas. Therefore, I would request the Minister to go out of his way to help the border States and border districts, so that our defences which are already very good may become better, so that the people in NEFA, Nagaland, Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan may become persons who show the willingness and readiness to man our defence.

Lastly, I am told that there is some departmental committee in the income-tax department. It is a very good thing and I am glad we are having such committees. That committee decides the promotion of employees in the income-tax department. I congratulate the Finance Minister on having such committees, which decide such questions, so that these questions are not agitated by individual employees. But the recommendations of that committee are held up in the UPSC and nothing has

[सेठ अचल सिंह]

बजट को ठीक बनायें और डेफ़िसिट न रखें। वह इनडायरेक्ट टैक्स लगायें, ताकि व्यापारी और आम जनता को दिक्कत का सामना न करना पड़े।

**श्री गणपति राम** (जौनपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि देश समाजवाद की तरफ प्रगति करे।

मेरे पूर्व-वक्ता, श्री पहाड़िया, का भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ, जिस में उन्हों ने माननीय सदस्य, पंडित भार्गव और हमारे प्रधान मंत्री जी के भाषणों के उद्धरण दिये। सुना है कि हमारे बुजुर्ग सदस्य ने सदन मे यह कहा था कि अमुक जातियों ने चुनावों में फ़लां पार्टी को वोट दिया और फ़लां पार्टी को वोट नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह सदन जातीयता का प्रचार करने के लिये कोई प्लैटफ़ार्म है। हालांकि मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन जिस तरीके से बातें कही गईं, उस से मुझे आश्चर्य हुआ।

मुझे यह भी सुन कर आश्चर्य हुआ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा बताते हैं कि हम योग्यता के आधार पर ही हरिजनों को नौकरियों में लेना चाहते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सब से अच्छी बात है, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक यह पूछता हूं कि योग्यता के आधार पर भी जहां हरिजनों को नहीं लिया जाता है और योग्यता के रहते हुए भी उन को अयोग्य साबित कर दिया जाता है, क्या सरकार एक कमीशन बिठा कर उन सब नौकरियों की जांच-पड़ताल करा सकती है कि संविधान लागू होने के बाद इन बारह बरसों में क्या सभी हरिजन अयोग्य ही साबित हुए और इसी लिये वे नौकरियों में नहीं लिये गये तथा रिज़र्वेशन होते हुए भी किसी भी विभाग या मिनिस्ट्री में रिज़र्वेशन का कोटा पूरा नहीं किया गया।

आज कहा जाता है कि सर्विस के लिये अनुभव होना चाहिये। सरकारी सर्विसिज़ में किसी विभाग में छः महीने का और किसी में साल भर का अनुभव रखा गया है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो हरिजन युगों से सेवा-कार्य कर रहे हैं, उन को सेवा के ही क्षेत्र में अयोग्य साबित कर दिया जाये। देश भर में जितनी जगहों पर हरिजन रखे गये, क्या वे सब अयोग्य साबित हुए और अगर उन को जान-बूझ कर अयोग्य साबित किया गया, तो क्या ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की गई और क्या उन लोगों पर उस का कोई नियत्रण रक्खा गया।

उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुश्किल से चालीस पचास पी० सी० एस० और पी० पी० एस० हरिजन आफ़िसर हैं, लेकिन उन में से भी आधे या तीन-चौथाई लोगों को कान्फिडेंशल रिपोर्ट खराब कर दी गई, ताकि उन का प्रोमोशन न हो। एक, दो, चार, दस आदमी अयोग्य हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे हरिजन आफ़िसर अयोग्य साबित हुए कि उन की कान्फिडेन्शल रिपोर्ट खराब कर के उन की प्रोमोशन का रास्ता खत्म कर दिया गया ? ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया, जो हमेशा उन के हुकूक को लेते रहे हैं। जिन लोगों ने इन हरिजन आफ़िसर्ज को अयोग्य दिखाने की कोशिश की और उन को ग़लत तरीके से कहीं डीमोट किया और कहीं कान्फ़िडेंशल रिपोर्ट खराब की, क्या उन के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं

they have lost on account of the Finance Commission is made good in an ample measure by the Finance Minister.

Mention was made about the roads. May I tell you that I myself have gone or travelled by the Bhimbher-Shopian road twice? Therefore, that road also has some association for me, and if anybody says that that road should not be built, I would say that that gentleman does not know the beauty of that road. I have trod every inch of that road on foot. Of course, I used to go by that road when I was a little boy. In 1943-45, I went on foot along that road, and I have some ties with that road. I think that one of the wise things that the Jammu and Kashmir State is doing is to rebuild that road. I agree with Shri Raghunath Singh that the Kangra-Kishtwar road should also be built. We want so many other alternative routes to Kashmir. Kashmir is a very sensitive point, so far as defence goes....

**16 hrs.**

**Shri Tyagi** (Dehra Dun): How would the hon. Member react to the suggestion that the Kashmir State must be brought into line with the other States constitutionally, so that it may be at par with U.P. and the other States?

**Shri D. C. Sharma:** That is what they also want. I think that will be done and that is being done. I thank the Finance Minister for being generous to the State. This shows how alert he is to our national needs, how vigilant he is about the defence of our county and how in spite of the fact that other things are also necessary, he has been so particular about defence.

So far as defence is concerned, of course, defence should be there in terms of Army, Navy and Air Force; I do not deny that our defence is well looked after these days. But when we talk of defence, we should talk of border States, border districts and border areas. Unless you look upon this as an integrated whole, I think the whole planning for development will not be very fruitful. For instance, take Punjab. It is a border State. Rajasthan is a border State. Gurdaspur is a border district which connects Punjab with Jammu and Kashmir; it is the gateway to Jammu and Kashmir.

Planning requires that you do not always adopt the rule of the thumb methods in the allocation of money. Planning should have a little imagination. When you employ a little imagination, you will find that the border States like Rajasthan and Punjab and border districts like Gurdaspur and Amritsar deserve special-nation treatment at the hands of the Finance Minister. I have been told about the inaccessible areas committee, hill areas committee, etc. We have so many committees and I do not object to them. But I am doubtful about the advantages which will flow from the committees to these areas. Therefore, I would request the Minister to go out of his way to help the border States and border districts, so that our defences which are already very good may become better, so that the people in NEFA, Nagaland, Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan may become persons who show the willingness and readiness to man our defence.

Lastly, I am told that there is some departmental committee in the income-tax department. It is a very good thing and I am glad we are having such committees. That committee decides the promotion of employees in the income-tax department. I congratulate the Finance Minister on having such committees, which decide such questions, so that these questions are not agitated by individual employees. But the recommendations of that committee are held up in the UPSC and nothing has

[सेठ अचल सिंह]

बजट को ठीक बनायें और डेफ़िसिट न रखें । वह इनडायरेक्ट टैक्स लगायें, ताकि व्यापारी और आम जनता को दिक्कत का सामना न करना पड़े ।

**श्री गणपति राम** (जौनपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि देश समाजवाद की तरफ प्रगति करे ।

मेरे पूर्व-वक्ता, श्री पहाड़िया, का भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ, जिस में उन्हों ने माननीय सदस्य, पंडित भार्गव और हमारे प्रधान मंत्री जी के भाषणों के उद्धरण दिये । सुना है कि हमारे बुजुर्ग सदस्य ने सदन मे यह कहा था कि अमुक जातियों ने चुनावों में फ़लां पार्टी को वोट दिया और फ़लां पार्टी को वोट नहीं दिया । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह सदन जातीयता का प्रचार करने के लिये कोई प्लैटफ़ार्म है । हालांकि मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन जिस तरीके से बातें कही गईं, उस से मुझे आश्चर्य हुआ ।

मुझे यह भी सुन कर आश्चर्य हुआ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा बताते हैं कि हम योग्यता के आधार पर ही हरिजनों को नौकरियों में लेना चाहते हैं । यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सब से अच्छी बात है, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक यह पूछता हूं कि योग्यता के आधार पर भी जहां हरिजनों को नहीं लिया जाता है और योग्यता के रहते हुए भी उन को अयोग्य साबित कर दिया जाता है, क्या सरकार एक कमीशन बिठा कर उन सब नौकरियों की जांच-पड़ताल करा सकती है कि संविधान लागू होने के बाद इन बारह बरसों में क्या सभी हरिजन अयोग्य ही साबित हुए और इसी लिये वे नौकरियों में नहीं लिये गये तथा रिजर्वेशन होते हुए भी किसी भी विभाग या मिनिस्ट्री में रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं किया गया ।

आज कहा जाता है कि सर्विस के लिये अनुभव होना चाहिये । सरकारी सर्विसिज़ में किसी विभाग में छः महीने का और किसी में साल भर का अनुभव रखा गया है । लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो हरिजन युगों से सेवा-कार्य कर रहे हैं, उन को सेवा के ही क्षेत्र में अयोग्य साबित कर दिया जाये । देश भर में जितनी जगहों पर हरिजन रखे गये, क्या वे सब अयोग्य साबित हुए और अगर उन को जान-बूझ कर अयोग्य साबित किया गया, तो क्या ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की गई और क्या उन लोगों पर उस का कोई नियत्रण रक्खा गया ।

उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुश्किल से चालीस पचास पी० सी० एस० और पी० पी० एस० हरिजन आफ़िसर हैं, लेकिन उन में से भी आधे या तीन-चौथाई लोगों की कान्फिडेंशल रिपोर्ट खराब कर दी गई, ताकि उन का प्रोमोशन न हो । एक, दो, चार, दस आदमी अयोग्य हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे हरिजन आफ़िसर अयोग्य साबित हुए कि उन की कान्फिडेन्शल रिपोर्ट खराब कर के उन की प्रोमोशन का रास्ता खत्म कर दिया गया ? ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया, जो हमेशा उन के हुकूक को लेते रहे हैं । जिन लोगों ने इन हरिजन आफ़िसर्ज को अयोग्य दिखाने की कोशिश की और उन को ग़लत तरीके से कहीं डीमोट किया और कहीं कान्फ़िडेंशल रिपोर्ट खराब की, क्या उन के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं

की जा सकती है ? गोरखपुर में जी० एम० रेलवे आफिस है । वहां पर किसी अधिकारी को केवल इस नाते डिमोट किया गया और एक दो बार रिपोर्ट खराब की गई कि उसने हरिजनों के कोटे को गवर्नमेंट के सर्क्युलर के अनुसार गिन कर के मिनिस्ट्री के सामने रखा । इस की उस को पनिशमेंट दी गई कि उस ने यह क्यों किया । लेकिन जिन अधिकारियों ने उस के साथ ऐसा सलूक किया वे आज भी उच्च पदों पर आसीन हैं । इस हरिजन को मुझे मालूम है डिमोट कर के दूसरी जगह भेज दिया गया । आज जान बूझ कर हरिजनों को अयोग्य ठहराया जाता है और नौकरी में नहीं लिया जाता है । लेकिन ऐसे केसिस भी मेरे सामने हैं जहां पर दो दो और तीन तीन साल तक चाहे योग्य हरिजन मिलता भी है, जगह को खाली रखा जाता है, भरा नहीं जाता है । पोस्ट्स एडवरटाइज़ की जाती हैं, एप्लीकेशंज़ आती हैं, सिलैक्शन होता है। गवर्नमेंट का लाखों रुपया टी० ए० इत्यादि पर खर्च होता है, पेनल भी बना लिया जाता है और यह सब कुछ हो चुकने के बावजूद भी दो दो साल तक उस को नहीं लिया जाता है केवल इस बिना पर कि वह हरिजन हैं । अगर आज हमारे प्रधान मंत्री जी या दूसरे मंत्रीगण यह महसूस करते हैं कि हरिजन अयोग्य हैं, तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी । कर्मठता के नाम पर मामूली पोस्ट्स के लिये भी, चपड़ासी की पोस्ट के लिये, या क्लर्क की पोस्ट के लिये भी हरिजन को अयोग्य समझा जाता है । मैं समझता हूं कि यह केवल उन को नौकरी में न लेने का बहाना मात्र है ।

हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि दस वर्ष का रिजर्वेशन खत्म होने के बाद एक कमिशन बैठे जो हर विभाग की जांच करे कि कितने हरिजन लिये गये हैं और क्यों कोटे के मुताबिक उन को नहीं लिया गया है और अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे । मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री जी से तथा वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमिशन बैठे जो यह देखे कि विभिन्न मंत्रालयों में जब से यह संविधान लागू हुआ है और जिस को लागू हुए बारह साल हो गये हैं, तब से अब तक कितने हरिजन रखे गये हैं और अगर वे कोटे के मुताबिक नहीं रखे गये हैं तो क्यों नहीं रखे गये हैं । जब वह अपनी रिपोर्ट दें तो उस को सदन के सामने पेश किया जाये । आज से दस साल पहले सन् १९५२ में जब हम लोग चुन कर आये थे उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो उस समय के रेल मंत्री थे, सदन के सदस्यों की मांग पर शायद एक बार रिपोर्ट निकाली थी, और उस के बाद से आज तक कोई रिपोर्ट इस सदन के समक्ष पेश नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि हमें बतलाया जाये कि पिछले बारह वर्षों में क्या प्रगति हुई है ।

उत्तर प्रदेश में मुझे हरिजन डायरेक्टोरेट देखने को मिला । मैंने वहां देखा है कि जितने भी अधिकारी हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह सभी नान-हरिजन हैं । वहां पर एक हरिजन आफिसर भी था जोकि रूल्ज़ को प्वांट आउट करता था उस को इस वजह से निकाला गया कि वह हरिजनों के मामलों में दखल देता था और रूल्ज़ और रेग्युलेशंज़ को प्वाइंट आउट करता था । बड़ी कोशिश के बाद साल भर उस को अलग रख कर के फिर से लिया गया है । इस तरह की बातें नहीं होनी चाहियें ।

मैं जानना चाहता हूं कि प्रोमोशन के मामले में क्या हरिजनों को कोई रिजर्वेशन दी गई है, कोई रिजर्वेशन रखी गई है और अगर नहीं रखी गई है तो क्यों नहीं रखी

केसेज मेरे देखने में आये जिनमें किसानों ने अनियमित टैक्सेशन के खिलाफ टैक्स कलेक्टर के यहां अपील की तो फैसला हुआ कि सरकार सारी तम्बाकू को वापस ले ले। साल भर से फैसला हुआ पड़ा है लेकिन वह लोग वापस नहीं लेते हैं इसलिये कि तम्बाकू की पैदावार की मिकदार कम है लेकिन टैक्स वापसी का रुपया ज्यादा है। इस तरह के मैं पचासों केसेज बतला सकता हूं। वहां पर कि गरीबों पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर गलत तरीके से टैक्सेशन हो रहा है और इसका असर गरीब जनता पर गलत तरीके से पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर आप मांगेंगे तो मैं सौ पचास केसेज आप को दे सकता हूं।

**श्री मोरारजी देसाई** : मांगने की क्या जरूरत है, अगर आप को कुछ करवाना है तो देना चाहिये।

**श्री गणपति राम** : जी हां, मैं दूंगा आप को।

---

**16.32 hrs.**

## MESSAGE FROM THE PRESIDENT

**Mr. Speaker:** Before I call upon the Finance Minister, may I make an announcement to the House?

I have received the following message dated the 21st March, 1962, from the President:—

> "I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Lok Sabha for the Address I delivered to both the Houses of Parliament assembled together on the 12th March, 1962.".

---

**16·32½**

## GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

**The Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** Generally, in the general debate on the Budget, every subject is relevant. The presentation of this Budget has only a limited purpose, because the regular Budget will be presented before the new Parliament next month, and therefore, we have seen that the debate has also taken a limited shape.

But, as we have come out just from the elections, elections also have occupied a large part of the time during this debate as also in the debate on the President's Address. I do not want to take the time of the House in referring to the elections or to the various criticisms made as regards elections because the Prime Minister has dealt with this subject fully in the course of his reply to the debate on the President's Address, and I do not think that anything new has been said or requires to be said in that connection.

But I might mention one thing as regards the criticism that the functioning of Government has not been very satisfactory and that there is great discontent among the people all around. The elections have shown that in spite of a concerted effort to run down the Government in every place, in all sorts of ways, not depending upon facts but depending more on fables and caricatures and all that, the party which runs this Government has got a majority, and, therefore, the people have on the whole accepted that the criticism is not correct substantially. I cannot say that the criticism is not correct at all or that there is no truth in it, but on the whole that criticism has not been accepted by the people.

It is not possible for me at this stage to speak anything about the

की जा सकती है ? गोरखपुर में जी० एम० रेलवे आफिस है । वहां पर किसी अधिकारी को केवल इस नाते डिमोट किया गया और एक दो बार रिपोर्ट खराब की गई कि उसने हरिजनों के कोटे को गवर्नमेंट के सर्क्युलर के अनुसार गिन कर के मिनिस्ट्री के सामने रखा । इस की उस को पनिशमेंट दी गई कि उस ने यह क्यों किया । लेकिन जिन अधिकारियों ने उस के साथ ऐसा सलूक किया वे आज भी उच्च पदों पर आसीन हैं । इस हरिजन को मुझे मालूम है डिमोट कर के दूसरी जगह भेज दिया गया । आज जान बूझ कर हरिजनों को अयोग्य ठहराया जाता है और नौकरी में नहीं लिया जाता है । लेकिन ऐसे केसिस भी मेरे सामने हैं जहां पर दो दो और तीन तीन साल तक चाहे योग्य हरिजन मिलता भी है, जगह को खाली रखा जाता है, भरा नहीं जाता है । पोस्ट्स एडवरटाइज़ की जाती हैं, एप्लीकेशंज़ आती हैं, सिलैक्शन होता है। गवर्नमेंट का लाखों रुपया टी० ए० इत्यादि पर खर्च होता है, पेनल भी बना लिया जाता है और यह सब कुछ हो चुकने के बावजूद भी दो दो साल तक उस को नहीं लिया जाता है केवल इस बिना पर कि वह हरिजन हैं । अगर आज हमारे प्रधान मंत्री जी या दूसरे मंत्रीगण यह महसूस करते हैं कि हरिजन अयोग्य हैं, तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी । कर्मठता के नाम पर मामूली पोस्ट्स के लिये भी, चपड़ासी की पोस्ट के लिये, या क्लर्क की पोस्ट के लिये भी हरिजन को अयोग्य समझा जाता है । मैं समझता हूं कि यह केवल उन को नौकरी में न लेने का बहाना मात्र है ।

हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि दस वर्ष का रिजर्वेशन खत्म होने के बाद एक कमिशन बैठे जो हर विभाग की जांच करे कि कितने हरिजन लिये गये हैं और क्यों कोटे के मुताबिक उन को नहीं लिया गया है और अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे । मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री जी से तथा वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमिशन बैठे जो यह देखे कि विभिन्न मंत्रालयों में जब से यह संविधान लागू हुआ है और जिस को लागू हुए बारह साल हो गये हैं, तब से अब तक कितने हरिजन रखे गये हैं और अगर वे कोटे के मुताबिक नहीं रखे गये हैं तो क्यों नहीं रखे गये हैं । जब वह अपनी रिपोर्ट दें तो उस को सदन के सामने पेश किया जाये । आज से दस साल पहले सन् १९५२ में जब हम लोग चुन कर आये थे उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो उस समय के रेल मंत्री थे, सदन के सदस्यों की मांग पर शायद एक बार रिपोर्ट निकाली थी, और उस के बाद से आज तक कोई रिपोर्ट इस सदन के समक्ष पेश नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि हमें बतलाया जाये कि पिछले बारह वर्षों में क्या प्रगति हुई है ।

उत्तर प्रदेश में मुझे हरिजन डायरेक्टोरेट देखने को मिला । मैंने वहां देखा है कि जितने भी अधिकारी हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह सभी नान-हरिजन हैं । वहां पर एक हरिजन आफिसर भी था जोकि रूल्ज़ को प्वांट आउट करता था उस को इस वजह से निकाला गया कि वह हरिजनों के मामलों में दखल देता था और रूल्ज़ और रेग्युलेशंज़ को प्वाइंट आउट करता था । बड़ी कोशिश के बाद साल भर उस को अलग रख कर के फिर से लिया गया है । इस तरह की बातें नहीं होनी चाहियें ।

मैं जानना चाहता हूं कि प्रोमोशन के मामले में क्या हरिजनों को कोई रिजर्वेशन दी गई है, कोई रिजर्वेशन रखी गई है और अगर नहीं रखी गई है तो क्यों नहीं रखी

केसेज मेरे देखने में आये जिनमें किसानों ने अनियमित टैक्सेशन के खिलाफ टैक्स कलेक्टर के यहां अपील की तो फैसला हुआ कि सरकार सारी तम्बाकू को वापस ले ले। साल भर से फैसला हुआ पड़ा है लेकिन वह लोग वापस नहीं लेते हैं इसलिये कि तम्बाकू की पैदावार की मिकदार कम है लेकिन टैक्स वापसी का रुपया ज्यादा है। इस तरह के मैं पचासों केसेज बतला सकता हूं। वहां पर कि गरीबों पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर गलत तरीके से टैक्सेशन हो रहा है और इसका असर गरीब जनता पर गलत तरीके से पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर आप मांगेंगे तो मैं सौ पचास केसेज आप को दे सकता हूं।

**श्री मोरारजी देसाई** : मांगने की क्या जरूरत है, अगर आप को कुछ करवाना है तो देना चाहिये।

**श्री गणपति राम** : जी हां, मैं दूंगा आप को।

---

**16.32 hrs.**

## MESSAGE FROM THE PRESIDENT

**Mr. Speaker:** Before I call upon the Finance Minister, may I make an announcement to the House?

I have received the following message dated the 21st March, 1962, from the President:—

> "I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Lok Sabha for the Address I delivered to both the Houses of Parliament assembled together on the 12th March, 1962.".

---

**16.32½**

## GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

**The Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** Generally, in the general debate on the Budget, every subject is relevant. The presentation of this Budget has only a limited purpose, because the regular Budget will be presented before the new Parliament next month, and therefore, we have seen that the debate has also taken a limited shape.

But, as we have come out just from the elections, elections also have occupied a large part of the time during this debate as also in the debate on the President's Address. I do not want to take the time of the House in referring to the elections or to the various criticisms made as regards elections because the Prime Minister has dealt with this subject fully in the course of his reply to the debate on the President's Address, and I do not think that anything new has been said or requires to be said in that connection.

But I might mention one thing as regards the criticism that the functioning of Government has not been very satisfactory and that there is great discontent among the people all around. The elections have shown that in spite of a concerted effort to run down the Government in every place, in all sorts of ways, not depending upon facts but depending more on fables and caricatures and all that, the party which runs this Government has got a majority, and, therefore, the people have on the whole accepted that the criticism is not correct substantially. I cannot say that the criticism is not correct at all or that there is no truth in it, but on the whole that criticism has not been accepted by the people.

It is not possible for me at this stage to speak anything about the